fo"k; lwph

भारत-पाक वार्ता

भाजपा का वक्तव्य.................. 5
साक्षात्कार : यशवंत सिन्हा..... 6
काश! दोनों तरफ से तैयारी होती —बी. रमन........................ 10

लेख

कमजोर सरकार और बेबस लोग —संजय द्विवेदी................ 8
पेट भरने का कठिन सवाल —देविन्दर शर्मा................ 24
जनजातियों की तरक्की भरतचंद्र नायक................ 26

अन्य

झिंझोली प्रशिक्षण शिविर.......... 4
रेल दुर्घटनाएं........................... 12
बिहार : विपक्षी दलों का हंगामा. 14
नक्सलियों से लड़ाई.............. 28

रिपोर्ट

केरल का तालिबानीकरण......... 18
हरियाणा में बाढ़....................... 21

सम्पादक
çHkkr >k] lkln
सम्पादक मंडल
lR;iky
d- d- 'kek
lathó dqekj flUgk
पृष्ठ संयोजन
/keZUæ dkS'ky
fodkl lSuh
सम्पर्क
Mk- eqdthZ Lefr U;kl
ihih&66] lqcze.;e Hkkjrh ekxZ
ubZ fnYyh&110003
Qksu ua- +91¼11½&23381428
QSDl ¼ +91¼11½&23387887
lnL;rk grq ¼ +91¼11½&23005700
सदस्यता शुल्क
okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-
e-mail address
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

lEikndh;

कमलसंदेश

कांग्रेस ने कहा- चुप रहो 'बड़बोले सिंह'

dkंग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आजकल 'बड़बोले सिंह' हो गए हैं। उनकी पार्टी ने उन्हें कहा– ''फुलस्टाप''; आगे नहीं। बोलने पर रोक लगा दी। भाषा का अपना संस्कार होता है। संस्कारहीन भाषा से कोई भी राजनीतिज्ञ समाज में श्रद्धा का स्थान नहीं पा सकता है। भाषा का सम्मान होना चाहिए।

'अनर्गल' बातों को रखकर आप राजनीति में जनविश्वास तो नहीं; हां, जन–जन में आप मसखरेबाज के रूप में अवश्य प्रसिद्ध हो जायेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी महाराष्ट्र प्रांत से आते हैं। उनकी 'हिन्दी' मराठीयुक्त होती है, उनका आशय उनकी भाषा से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता है। उनकी भाषाई नीयत पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। अगर उनको कभी लगता है कि उनके वाक्य से कोई आहत हुआ तो 'वे' स्वयं खेद प्रगट कर लेते हैं। पर यहां तो दिग्विजय सिंह ने हद कर दी। 'वो' मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा के बारे में कहते हैं, ''उनकी औकात क्या है'? वे प्रदेश में आयातित हैं।'' अब यहां विचार करने वाली बात है कि क्या दिग्विजय सिंह को यह भाषा बोलनी चाहिए? इस बात पर हालांकि उन्हें प्रभात झा ने पत्र लिखकर कहा कि ''राजा साहब, हमारी सच में कोई औकात नहीं है। पर मेरी पार्टी की मध्यप्रदेश में बहुत बड़ी औकात है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और भी बहुत बड़ी औकात है। यही कारण है कि कांग्रेस को मध्यप्रदेश में भाजपा एक नहीं, दो–बार से जन–आस्था और जनमत से धूल चटा रही है।'' उन्होंने आगे अपने पत्र में लिखा कि बात रही आयातित नेता की, तो कम से कम हम तो बिहार में पैदा हुए हैं और भारतीय हैं। पर जरा अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा मैडम सोनिया जी के बारे में दिग्विजय सिंह जी आपके क्या विचार हैं, यह तो देशवासियों को बता दीजिए। दिग्विजय सिंह ने पत्र के बाद चुप्पी साध ली। बाद में एक पत्र लिखकर सफाई देने की कोशिश की, जो बेबुनियाद थी।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा था कि क्या संसद पर हमले के साजिशकर्ता अफजल गुरू कांग्रेस का रिश्तेदार लगता है। इसमें गलत क्या है? क्या इसका मतलब यह हो गया कि दिग्विजय सिंह आपे से बाहर हो जाएं। कतई ऐसा नहीं होना चाहिए था। अफजल गुरू और कसाब के बारे में न्यायालय से आदेश हो जाने के बाद भी उन्हें फांसी क्यों नहीं दी जा रही? कौन रोके बैठा है? भारत सरकार के गृहमंत्री अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करते? क्या भारत माता पर हमला करने वालों को, जिन्हें न्यायाधीशों ने ''सजा–ए–मौत'' का फैसला सुनाया है, उसे वर्षों से ''वोट बैंक'' के लिए फांसी नहीं देनी चाहिए? न्याय व्यवस्था पर कौन विश्वास करेगा? साथ ही देश आतंकवाद से कैसे लड़ेगा? आतंकवाद के पसरते साम्राज्य के लिए सिर्फ वर्तमान यूपीए सरकार और खासकर कांग्रेस जिम्मेदार है। भारतमाता का सच्चा सपूत जो मातृभूमि के लिए काम करता है, ऐसे करोड़ों मातृभक्तों के मुंह से वही बात निकलेगी जो भाजपा के

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के मुंह से निकली।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते हैं कि नक्सलियों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पैसा मिलता है। कितना घटिया आरोप? कोई भी भारतीय रा.स्व. संघ के बारे में सपने में भी इतनी बुरी बात नहीं सोच सकता। श्री दिग्विजय सिंह के इस बयान से दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक यह कि श्री दिग्विजय सिंह के नक्सलियों से संबंध हैं या फिर उनके आरएसएस से गहरे संबंध हैं। अब उन्हें बताना होगा कि उनके किससे संबंध हैं नक्सलियों से या संघ से।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है जो भारत, भारतीयता और भारत माता के साथ–साथ प्रत्येक राष्ट्रवादी विचारधारा वालों के साथ खड़ी है, जो भारत माता में अपनी आस्था रखता है। आज 'संघ' ने देश के करोड़ों लोगों में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है।

संघ की स्थापना को 85 वर्ष हो गए। संघ ने अपने कार्यों से देश में साख और धाक बनाई है। क्या किसी ऐसी संस्था के बारे में इस तरह की बात कहनी चाहिए? कदापि नहीं। दिग्विजय सिंह जी चूक गए। उन्हें तथ्यहीन और आधारहीन बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वे एक जिम्मेदार नेता हैं, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी देश का एक जिम्मेदार सांस्कृतिक संगठन है। किसी भी संगठन और संस्था की छवि के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस ने कहा– ''दिग्विजय सिंह'' चुप रहो। अनर्गल मत बोलो।'' दिग्विजय सिंह जी आप सही होते तो कांग्रेस ऐसा नहीं बोलती। ■

राजनीतिक कार्यकर्ताओं की दक्षता के लिए अध्ययन और अभ्यास जरूरी : गडकरी

झिंझौली में तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के पश्चात भाजपा ने अगले एक माह में सभी 10 हजार पोलिंग बूथों पर एक लाख निष्ठावान कार्यकर्त्ताओं को तैयार करने का संकल्प लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटित भाजपा के 13 सत्रीय अभ्यास वर्ग का समापन दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री बिजेन्द्र गुप्ता के सम्बोधन से हुआ।

भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजित, तीन दिवसीय अभ्यास वर्ग का उद्घाटन दिल्ली के निकट झिंझौली गांव में 9 जुलाई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए श्री नितिन गडकरी ने कहा कि पार्टी ने जो कल्पना इंदौर के राष्ट्रीय अधिवेशन में की थी उसे आज दिल्ली भाजपा की इकाई ने साकार किया है। उन्होंने प्रशिक्षण की धारणा स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति किसी भी व्यवसाय या प्रोफेशन में यदि दक्षता पाना चाहता है तो उसे लगातार अध्ययन, अभ्यास तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। आज विभिन्न प्रकार के प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, वकील आदि अपने आपको निपुण बनाये रखने के लिए और सामयिक जानकारियां पाने के लिए, विभिन्न प्रकार के अध्ययन एवं अभ्यास करते रहते हैं तथा अनेकों प्रकार के अभ्यास वर्गों में हिस्सा लेते रहते हैं। जिसमें वे अपने प्रोफेशन में निपुणता/महारत हासिल करने में सफल होते हैं।

भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने यह अभ्यास वर्ग कुछ चुने हुये कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया था। इस वर्ग में प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष एवं महामंत्री, मोर्चा अध्यक्ष एवं महामंत्री, मंडल अध्यक्षों को सम्मिलित किया गया था। इस अभ्यास वर्ग के एक अन्य सत्र में राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरूण जेटली ने पार्टी कार्यकर्ताओं को विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों से अवगत कराया। जिसमें कश्मीर में आतंकवाद और भारत वर्ष के लगभग 210 जिलों में माओवादी, नक्सली समस्या के बारे में विस्तार से चर्चा थी। श्री जेटली ने युवाओं के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जिस प्रकार अमेरिका और ब्रिटेन में 50 वर्ष की आयु वाले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने है तो ऐसा भारत में क्यों नहीं हो सकता है।

अभ्यास वर्ग में राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन), श्री रामलाल, श्री थावरचंद गहलौत, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, राष्ट्रीय मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना एवं श्री विनय सहस्त्रबुद्धे सहित अनेक भाजपा विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन किया। वरिष्ठ वक्ताओं ने कहा कि जैसे हीरे को तराशना पड़ता है। तभी वह कीमती हीरा बनता है। उसी प्रकार कार्यकर्ता को भी संवारने की आवश्यकता रहती है। अभ्यास वर्ग से ही वह अपने मूल मंत्रों, संयम, समन्वय, संघर्ष व सेवा का वाहक और निष्ठावान प्रहरी बनता है।

भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि एक व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों न हो पूरे सम्मिलित समाज से बलवान नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने–अपने क्षेत्रों में 'एक सबके लिए और सबके लिए एक' का सिद्धान्त अपनाना होगा हमें भरोसा है कि भाजपा का भविष्य भी इसके स्वर्णिम अतीत की तरह देश के राजनीतिक क्षितिज पर दैदीप्यमान होगा।■

कमल संदेश

पाकिस्तान के साथ बातचीत का मुख्य मुद्दा आतंकवाद हो : भाजपा

श्री राजीव प्रताप रूड़ी, सांसद एवं भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा 20 जुलाई को जारी प्रेस वक्तव्य

ikकिस्तान के हठधर्मी रवैये और पाकिस्तान विदेशी मंत्री की बदजुबानी इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि पाकिस्तान भारत के साथ सौजन्यतापूर्ण तथा शांतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए जरा भी गम्भीर नहीं है। स्पष्ट है कि पाकिस्तान केवल बातचीत करने की मात्र बातें ही करता है तो दूसरी तरफ वह भारत के खिलाफ अपनी धरती से आतंकवादियों को बेखौफ संरक्षण देने और उनका बचाव करके अपने विनाशकारी एजेण्डा पर चल रहा है। पाकिस्तान लचर बातें और भारत की तरफ उंगली उठाने के अलावा उन व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कोई भी दृढ़ और ठोस कार्रवाई करने के मामले में जरा भी गम्भीर दिखाई नहीं पड़ता है, जो भारत में आतंक भड़काने का काम कर रहे हैं जबकि भारत ने इनके खिलाफ हर तरह के प्रमाण प्रस्तुत कर दिए हैं जिनमें डेविड हेडली द्वारा घृणित रहस्यों का उद्घाटन भी शामिल है।

हाल में जिन रहस्यों का उद्घाटन हुआ है, उनसे पाकिस्तान नौ सेना द्वारा मुम्बई हमलों में आतंकवादियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें सुविधा प्रदान करने का पता चल जाता है जिससे इस सम्बंध में पाकिस्तान का झूठ बार–बार सामने आता है। यह भी मालूम हुआ है कि आईएसआई का मुखिया ले. जन. अहमद शुजा पासा ने मुम्बई हमलों के मास्टरमाइंड और एलईटी के सरदार जैसे व्यक्तियों से हाल में जेल में मुलाकात की थी।

लगता है कि मुम्बई हमलों में आईएसआई और पाकिस्तान नौसेना द्वारा प्रशिक्षण और सुविधा प्रदान करने में सीधा हाथ होना एक प्रमुख कारण बन गया है कि अचानक ही हाल की बातचीत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दुराग्रही और लड़ाकू रवैया अपना लिया है। स्पष्ट है कि पाकिस्तान अपनी धरती से फैले आतंकवाद के बारे में भारत की चिंताएं दूर करने में कोई रूचि नहीं रखता है और अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के कारण मुम्बई अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का बहाना मात्र बना रहा है, जबकि पर्दे के पीछे से वह यही सुनिश्चित करने में लगा है कि उनके खिलाफ कोई सार्थक कार्रवाई न हो।

भाजपा महसूस करती है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के मसले को सीधे इस बात के साथ जोड़ा जाए कि पाकिस्तान सरकार आतंकवादियों के खिलाफ, विशेष रूप से मुम्बई हमले के अपराधियों के खिलाफ कोई विश्वसनीय कार्रवाई करती है या नहीं? पाकिस्तान के गम्भीर रवैये को देखते हुए भारत सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान सरकार के साथ तभी बातचीत की जाए जब वह अपने रवैये में परिवर्तन कर कोई विश्वसनीय संकेत दे।

भाजपा सरकार को स्मरण कराना चाहेगी कि वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पाकिस्तान में भारत–विरोधी आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की विश्वसनीय कार्रवाई और प्रगति होने के साथ बातचीत को जोड़ा था और इसका लाभ भी प्राप्त होना शुरू हुआ था और पाकिस्तान को कठघरे में भी खड़ा किया गया था। एनडीए सरकार पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए बड़े पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीय सहमति तैयार करने में भी सफल हुई थी ताकि पाकिस्तान सक्रिय कार्रवाई करे। उस

भाजपा महसूस करती है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के मसले को सीधे इस बात के साथ जोड़ा जाए कि पाकिस्तान सरकार आतंकवादियों के खिलाफ, विशेष रूप से मुम्बई हमले के अपराधियों के खिलाफ कोई विश्वसनीय कार्रवाई करती है या नहीं? पाकिस्तान के गम्भीर रवैये को देखते हुए भारत सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान सरकार के साथ तभी बातचीत की जाए जब वह अपने रवैये में परिवर्तन कर कोई विश्वसनीय संकेत दे।

शेष पृष्ठ 12 पर...

पाकिस्तान की अनदेखी शुरू करे भारत : यशवंत सिन्हा

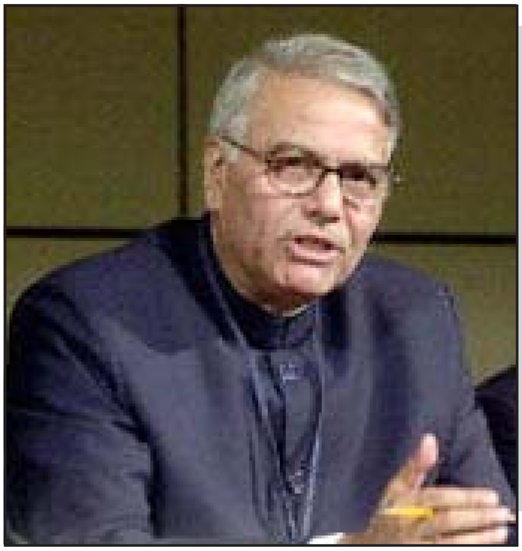

भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सांप–सीढ़ी के खेल की तरह हैं। यहां रिश्तों को आगे ले जाने वाली सीढियां कम नजर आती हैं और नीचे धकेलने वाले सांप ज्यादा। कारगिल हो या 26/11 को हुआ मुंबई का आतंकी हमला, भारत ने जब भी अपने जख्मों को भुलाकर दोस्ती की नई पहल की तो उसके अनुभव कसैले रहे। ऐसे में दोनों देशों के बीच बातचीत और संबंधों के समीकरण समझने के लिए भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा से। दैनिक जागरण के विशेष संवाददाता प्रणय उपाध्याय और राजकिशोर की बातचीत के संक्षिप्त अंश–

भारत को दोस्ती का हाथ बढ़ाने पर पाकिस्तान से अपमान क्यों झेलना पड़ता है और इस्लामाबाद में हुई ताजा दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों के संबंधों को आप कहां खड़ा देखते हैं?

भारत और पाकिस्तान के सबंधों का एक इतिहास है। लाहौर बस यात्रा के बाद कारगिल मिला। आगरा के बाद संसद पर हमला, लेकिन हर बार भारत पर ही हमेशा बड़प्पन का दबाव रहता। अपेक्षा रहती है कि पाकिस्तान भले ही कुछ भी व्यवहार करे, लेकिन हमें शालीनता दिखानी है। इसके कारण एक अव्यावहारिक दृष्टिकोण पैदा होता है। हमने भी गलती की। इस इतिहास को भुलाकर हमने बिना पूरी तैयारी के मुशर्रफ को आगरा आमंत्रित किया, बैठक विफल रही। भारत बार–बार वही गलती दुहरा रहा है। जिसने भी परवेज मुशर्रफ की किताब लाइन ऑफ फायर पढ़ी है उसको आसानी से यह अंदाज होगा कि पाकिस्तानी फौज और उसके हुक्मरान भारत के बारे में क्या दृष्टिकोण व नीयत रखते हैं। उनके रवैये के कारण ही इस बार की बातचीत भी न केवल बेनतीजा रही, बल्कि आज दोनों देशों के बीच मतभेद और बढ़े हैं तथा विश्वास का संकट अधिक गहराया है।

चूक कहां हुई और क्या विदेश मंत्री कृष्णा भारत के हितों की हिफाजत करने में कामयाब रहे?

बंद कमरे की बातचीत का ब्यौरा तो सरकारी फाइलों में होगा, लेकिन जो साझा पत्रकार वार्ता में हुआ उसे देखकर लगता है कि शायद विदेश मंत्री कृष्णा भारत के हितों को पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख पाए। हाफिज सईद जैसे आतंकी से भारत के गृह सचिव की तुलना अपने आप में बहुत अपमानजनक है, लेकिन मंच पर कृष्णा की चुप्पी सवाल खड़े करती है। भारतीय विदेश मंत्री की मौजूदगी में बातचीत को समग्र वार्ता करार दिया गया, जबकि भारत समग्र वार्ता को खारिज करता रहा है। वहीं कृष्णा की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान 26/11 के मुंबई हमले के गुनहगारों पर कार्रवाई के लिए भारतीय मजिस्ट्रेट को गवाही की खातिर पाक बुलाने जैसी बातें कही गईं जिनका कोई प्रतिकार नहीं हुआ। जहां तक चूक का सवाल है तो भारत–पाक वार्ता में सबसे महत्वपूर्ण काम है अपेक्षाओं का प्रबंधन। भारत और पाकिस्तान के नेताओं की मुलाकात एक ऐसा विषय है जिस पर इन दोनों मुल्कों के लोगों की ही नहीं दुनिया भर की निगाहें होती हैं। लिहाजा यह बहुत जरूरी है कि वार्ता के नतीजों को लेकर अपेक्षाएं संतुलित रखी जाएं। अगर वार्ता में बात

नहीं बन पाई थी भारत को खुली पत्रकार वार्ता से परहेज करना चाहिए था।

आप विदेश मंत्रालय में रहे हैं और इन तमाम कमजोरियों से भी वाकिफ हैं। भारत के पाकिस्तान के साथ बातचीत की मेज पर जाने को लेकर अमेरिकी दबाव कितना रहता है?

अमेरिका की चिंता अफगानिस्तान में उसका अभियान है। वाशिंगटन चाहता है कि अफगान अभियान के लिए उसे पाक की मदद मिलती रहे, जबकि पाक भारत का हौवा दिखाकर अमेरिका को यह दिखाने की कोशिश करता है कि नई दिल्ली के खतरे के कारण कारण वह ज्यादा मदद नहीं दे पाएगा। अमेरिका का दबाव होता है कि भारत कोई बवाल न करे और यदि थोड़ी बहुत आतंकी घटनाएं होती भी हैं तो उन्हें सहन करे। इसी का फायदा उठाकर पाक जब बातचीत करने आता है तो एक ऊंचे पायदान से चढ़ कर बात करता है। इसका नजारा विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के साथ इस्लामाबाद में हुई साझा पत्रकार वार्ता में भी साफ था, जहां पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी दंभ और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंग्थ से बात कर रहे थे।

आपकी नजर में ताजा दौर की बातचीत की नाकामी के बाद आगे का रास्ता कठिन होगा? क्या इस मामले को विपक्ष संसद में उठाएगा?

निश्चित रूप से। विदेश नीति का एक ऐसा मसला है जिससे देश का आम आदमी भी सीधे जुड़ा है और वह है पाकिस्तान का। पाक विदेश मंत्री ने जो रवैया दिखाया उसे लोग नहीं भूल सकते। जहां तक संसद का सवाल है तो एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई है और जाहिर तौर पर यह अपेक्षा होगी कि इस बारे में सरकार बयान दे जिस पर संसद में चर्चा हो।

भारत-पाक संबंधों को लेकर आगरा से लेकर शर्म अल शेख तक हर बार क्या हमारे नेता महानता के मोह में फंस जाते हैं? आपकी नजर में पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर अमेरिका का दबाव ज्यादा है या महानता का?

आपने ठीक कहा। हम महानता के दबाव में फंसते हैं। मेरी नजर में मनमोहन सिंह पर भी महानता का ही दबाव ज्यादा है। यह दिखाने की कोशिश है कि मैंने देश की कई मुश्किलें हल कीं और इतनी बड़ी समस्या का भी समाधान निकाल दिया। यह नहीं भूलना चाहिए कि महानता का ओढ़ा हुआ दबाव अक्सर नुकसानदेह साबित होता है।

...परंतु बातचीत न करना क्या विकल्प है? क्योंकि जिस भी सरकार में यह प्रयोग हुआ उसे बाद में पाक की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ा।

बातचीत न करना भी एक कूटनीतिक हथियार है। हमारी ओर से हर बार जो यह कहा जाता है कि बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, इस रवैये को छोड़ना होगा। इसके अलावा यह आशंका भी छोड़नी होगी कि बातचीत नहीं तो केवल युद्ध ही विकल्प है। पाकिस्तान की छद्म युद्धनीति और आतंकवाद के खिलाफ सबसे कारगर हथियार होगा कि हम अपनी सीमाओं को एकदम सुरक्षित बनाएं। निगरानी तंत्र कड़ा करें और वह हमारे खिलाफ आतंकवाद को हथियार की तरह इस्तेमाल न कर सकें। उसके बाद पाकिस्तान को नजरअंदाज करना शुरू करना चाहिए। जाहिर तौर पर पाकिस्तान शोर मचाएगा, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि आज का भारत और दुनिया में उसकी हैसियत 1947 ही नहीं 1999 से काफी अलग है।

...लेकिन क्या भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद समस्याओं का कोई समाधान नहीं है?

मैं आपसे पूछता हूं, क्या समाधान होगा? सियाचिन का समाधान संभव है, सरक्रीक का हल निकल सकता है। व्यापार, वाणिज्य और पानी की समस्याओं का भी हल ढूंढा जा सकता है। यहां तक कि आतंकवाद का भी समाधान हो सकता है, लेकिन उनके लिए असली मुद्दा है कश्मीर। हम भले ही सीमाओं को न बदलने की और नियंत्रण रेखा को अप्रासंगिक करने की बात करें, लेकिन पाकिस्तान में भारत की नीयत को लेकर बहुत गहरी आशंकाएं हैं। साथ ही पाकिस्तानी हुक्मरानों से बातचीत में यह नहीं भूलना चाहिए कि हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनका संचालन वहां की फौज करती है।■

साभार : पत्रिका

बहादुर सेना, कमजोर सरकार और बेबस लोग!

&lit; f}onh

fnल्ली में क्या इससे कमजोर सरकार कभी आएगी? कमजोर इसलिए क्योंकि इस सरकार के लिए देश के सम्मान, देश की जनता के जान–माल और हमारे सेना–सुरक्षा बलों की जान की कोई कीमत नहीं है। हो सकता है कि हालात इससे भी बुरे हों। किंतु अब यह कहने में कोई संकोच नहीं कि दिल्ली में इतनी बेचारी, लाचार और कमजोर सरकार आज तक नहीं आयी। थोपे गए नेतृत्व और स्वाभाविक नेतृत्व का अंतर भी इसी परिघटना में उजागर होता है। दिल्ली में एक ऐसे आदमी को देश की कमान दी गयी है जो आर्थिक मामलों पर जब बोलता है तो दुनिया सुनती है (बकौल बराक ओबामा)। किंतु उसके अपने देश में पिछले छः सालों से उसके राज में महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर रखा है किंतु वह आदमी अपने देश की महंगाई पर कुछ नहीं बोलता। परमाणु करार विधेयक पास कराने के लिए अपनी सरकार तक गिराने की हद तक जाने वाले हठी प्रधानमंत्री को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनकी सरकार के कार्यकाल में लोगों का जिंदगी बसर करना कितना मुश्किल है और कितने किसान उनके राज में आत्महत्या कर चुके हैं। यह एक ऐसी सरकार है जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले पांच सालों में अकेले नक्सली आतंकवाद में ग्यारह हजार लोग मारे जा चुके हैं। वह इस बात पर विमर्श में लगी है कि सेना का इस्तेमाल हो या न हो। क्या ऐसा इसलिए कि नक्सली आतंक एक ऐसे इलाके में है जहां आम आदिवासी रहते हैं जिन्हें मिटाने और समाप्त करने का साझा अभियान नक्सली नेताओं और सरकार ने मिलकर चला रखा है। झारखंड से लेकर बस्तर तक की जमीन जहां उसके असली मालिक वनपुत्र और आदिवासी रहते हैं, एक युद्ध भूमि में तब्दील हो गयी है। जहां विदेशी विचार(माओवाद) और विदेशी हथियारों से लैस लोग 2050 तक भारतीय गणतंत्र पर कब्जे का स्वप्न देख रहे हैं। फिर भी हमारी सरकार को इस इलाके में सेना नहीं चाहिए। भले नक्सली तीन माह में सौ से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों को अकेले बस्तर में ही न मार डालें। वे हजारों करोड़ की लेवी वसूलते हुए इन जंगलों में लैंड माइंस बिछाते रहें और हमारा राज्य रोम के जलने पर नीरो की तरह बांसुरी बजाता रहे।

दिल्ली में क्या इससे कमजोर सरकार कभी आएगी? कमजोर इसलिए क्योंकि इस सरकार के लिए देश के सम्मान, देश की जनता के जान–माल और हमारे सेना–सुरक्षा बलों की जान की कोई कीमत नहीं है। हो सकता है कि हालात इससे भी बुरे हों। किंतु अब यह कहने में कोई संकोच नहीं कि दिल्ली में इतनी बेचारी, लाचार और कमजोर सरकार आज तक नहीं आयी।

अब थोड़ा देश के मस्तक पर नजर डाल लें। यह जम्मू कश्मीर का इलाका है जो कभी धरती का स्वर्ग कहा जाता था। आज इस क्षेत्र को हमारी सरकारों की घुटनाटेक और कायर नीतियों ने घरती के नरक में बदल दिया है। हमारी सेना के अलावा इस पूरे इलाके में भारत मां की जय बोलने वाला कोई नहीं बचा है। कश्मीर के पंडितों के विस्थापन के बाद इस पूरे इलाके में पाकपरस्त आतंकी संगठनों का हस्तक्षेप है। उनके रास्ते में सबसे बड़ी बाधक भारतीय सेना है। हमारी महान सरकार अब सेना के हाथ से भी कवच–कुंडल छीनने पर आमादा है ताकि कश्मीर में भारतीय राज्य की एक और पराजय सुनिश्चित की जा सके। इस काम में दिल्ली की सरकार बराबर की भागीदार है। कश्मीर के मुख्यमंत्री और उनके पिता का सर्वाधिक दबाव इस बात पर है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में बदलाव किया जाए। यह बदलाव क्यों किया जाए इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। किंतु बदलाव होने जा रहा है और प्रधानमंत्री ने उसे मंजूरी भी दे दी है। सेनाध्यक्षों के विरोध के बावजूद पाकिस्तान के झंडे और 'गो इंडियंस' का बैनर लेकर प्रदर्शन करने वालों को खुश

करने के लिए हमारी सरकार आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में बदलाव करने जा रही है। यह एक ऐसी सूचना है जो हर भारतीय को हतप्रभ करने के लिए काफी है। देश के साठ सालों बाद भी हमारी सरकार अपनी ही सेना के खिलाफ खड़ी है। क्या भारतीय की राजनीति इतनी दिशाहारा और थकाहारा हो चुकी है? क्या हमारी सरकारें अपना विवेक खो चुकी हैं? वे सेना को मानवता और संवेदनशीलता सिखा रही है। नए बदलाव में सेना शत्रु को पकड़ने और गोली चलाने का अधिकार खो देगी। फिर सेना की जरूरत ही क्या है। ऐसे हालात में कहीं यह कश्मीर को पाक को सौंप देनी की एक लाचार कवायद तो नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ जब हमें कड़े संदेश देने की जरूरत है तब हम अपनी सेना को ही कमजोर बनाना चाहते हैं। सच्चाई तो यह है कि हमारी सेना ने अनेक अवसरों पर अपने अप्रतिम साहस के प्रदर्शन से भारत के मान को बचाया है। जबकि राजनैतिक नेतृत्व सदा जमीनें छोड़ता, युद्धबंदियों को छोड़ता और समझौते करता आया है। इन्हीं समझौतों और वोट की कथित लालच ने हमारे नेताओं को इतना बेचारा बना दिया है कि हमारे नेता ही कहते हैं कि अगर अफजल गुरू को फांसी दी गयी तो कश्मीर सुलग जाएगा। तो आप बताएं इस समय कश्मीर क्यों सुलग रहा है। किसे फांसी दी गयी है। कश्मीर के नेता भारत के साथ रहने की कीमत वसूल रहे हैं। उन्हें इस देश से कोई लेना–देना नहीं है। नहीं तो वे विस्थापित हिंदुओं की वापसी की बात क्यों नहीं करते, पर उन्हें तो सेना की वापसी चाहिए ताकि वे आराम से पाकिस्तानी हुक्मरानों की गोद में जा बैठें। जो अब्दुला परिवार सालों से कश्मीरी राजनीति का सिरमौर बना है, भारत ने उनका इतना सम्मान किया पर वे आज अफजल गुरू की फांसी रोकने की अपीलें कर रहे हैं। दूसरा मुफ्ती परिवार भारतीय संविधान की शपथ लेकर देश का गृहमंत्री बनता है तो अपनी ही बेटी का अपहरण करवाकर आतंकियों की रिहाई का नाटक रचता है। दुर्भाग्य से ऐसे ही लोग भारत भाग्य विधाता बनकर बैठे हैं।

यह एक ऐसी सरकार है जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले पांच सालों में अकेले नक्सली आतंकवाद में ग्यारह हजार लोग मारे जा चुके हैं। वह इस बात पर विमर्श में लगी है कि सेना का इस्तेमाल हो या न हो।

इसी तरह पूर्वांचल के सात राज्यों का बुरा हाल है। असम से लेकर मणिपुर तक बुरी खबरें हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक हालात बदतर कर रखे हैं। हमारी सरकारें उनकी मिजाजपुर्सी में लगी हैं। राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं को सिर्फ पांच साल और वोट बैंक दिखता है। सो वे घुसपैठियों के राशन कार्ड बनवाने, मतदाता परिचय पत्र बनवाने और अवैध बस्तियां बसाने में सहयोगी बनते हैं। जाहिर तौर पर इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बहुत विकराल स्वरूप ले चुका है।

हम अपनी सेना और सुरक्षा बलों को लाचार बना कर पहले से तैयार बैठे शत्रुओं को अवसर सुलभ करा रहे हैं। अभी पाक प्रेरित आतंकवाद के लिए भी हमारी अपनी ताकत क्या है। हमारी सरकार को हर शिकायत लेकर अमरीका के दरबार में जाना पड़ता है। कल अगर सेना का भी मनोबल टूट गया तो उस दृश्य की कल्पना करना भी मुश्किल है कि हमारा क्या होगा। देश इस देश के लोगों का है, जो इसे बेबस निगाहों से देख रहे हैं।

यह देश अगर दलित, मुस्लिम और ईसाई जैसी राजनीतिक बोलियों से चलाया जाएगा तो इसे कोई बचा नहीं सकता। शायद इसीलिए हम देश का तेजी से विघटन होता देख रहे है। यह विघटन चरित्र का है, नैतिकता का है, देशभक्ति का भी है।

देश का राजनीतिक नेतृत्व किसी भी प्रकार का आदर्श प्रस्तुत कर पाने में विफल है। सारे संकटों में मौन ही हमारे राजनैतिक नेतृत्व का आदर्श बन गया है। आप देखें तो हाल के तीन बड़े संकटों भोपाल गैस त्रासदी, कश्मीर संकट और महंगाई पर देश की सबसे ताकतवर नेता सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आया है। ऐसा नेतृत्व क्या आपको संकटों से निजात दिला सकता है या आपकी जिंदगी के अँधेरों से मुक्ति दिला सकता है। प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद करना तो व्यर्थ ही है क्योंकि उनकी नजर में हम भारत के लोगों का कोई मतलब नहीं है। ऐसे घने अंधेरे में आशा की कोई किरण नजर आती है तो वह शक्ति जनता के पास ही है कि वह अपने राजनीतिक नेतृत्व पर कोई ऐसा दबाव बनाए जिससे वह कम से कम देश के हितों, सुरक्षा के साथ सौदेबाजी न कर सके। देश में एक ऐसा अराजनैतिक अभियान शुरू हो जहां देश सर्वोपरि है, इस भावना का विस्तार हो सके। वरना हमारी राजनीति हमें यूं ही बांटती, तोड़ती और कमजोर करती रहेगी। ■

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)

काश! दोनों तरफ से तैयारी हुई होती

&ch- jeu

Hkk रत के विदेश मंत्री एसएम कृष्णा और पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने 15 जुलाई को इस्लामाबाद में करीब छह घंटे तक बातचीत की। इस बीच कृष्णा ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात भी की, जिन्हें उम्मीद थी कि विदेश मंत्रियों की बैठक उसी तरह बिना कड़वाहट के संपन्न हो जाएगी, जैसी 25 और 26 जुलाई को भारत के गृहमंत्री पी. चिदंबरम और पाकिस्तान के गृहमंत्री रहमान मलिक और 24 जुलाई को भारत और पाक के विदेश सचिवों की मुलाकात हुई थी, वे जरूर निराश हुए होंगे। कड़वाहट छुप नहीं सकी और वह तब साफ तौर पर दिखी जब दोनों विदेश मंत्री अपनी चर्चा खत्म होने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। टीवी देखने वाले दोनों के चेहरों से नाराजगी साफ पढ़ सकते थे। इस बैठक का मकसद दोनों देशों के बीच विश्वास का माहौल बनाना था ताकि तमाम लंबित मुद्दों पर बातचीत की जा सके। इसके लिए 28–29 अप्रैल को थिंपू में आयोजित सार्क सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बीच सहमति हुई थी। जैसा कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने तय किया था कि इस बैठक का प्रस्तावित उद्देश्य रणनीतिक, सकारात्मक और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने वाला होगा। वह दोतरफा संबंधों में गतिरोध डालने वाला नकारात्मक नहीं होना चाहिए। किसी को यह लग सकता है कि दोनों विदेश मंत्रियों को पूरी तरह से कार्यनीतिक मामलों पर बात करनी चाहिए थी, न कि उन्हें उन तमाम कार्रवाइयों पर चर्चा करनी थी जिसके माध्यम से विश्वास कायम किया जा सकता है। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कृष्णा ने ठीक ही कहा कि 26/11 के पाकिस्तानी हमलावरों पर कार्रवाई करके पाकिस्तान विश्वास कायम करने का महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है, जबकि कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार जम्मू–कश्मीर के संबंध में विश्वास कायम करने वाले उन उपायों को लागू करने के लिए उत्सुक है, जो भारत सरकार से बातचीत के दौरान पाकिस्तान सरकार ने तय किए थे। उदाहरण के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार व्यापार को प्रोत्साहन।

कुरैशी ने विश्वास कायम करने वाले इन उपायों और भौगोलिक स्थिति को बदले बिना कश्मीर समस्या के हल के लिए राजनीतिक किस्म के उपायों में अंतर भी करके देखा। हालांकि उन्होंने जनरल मुशर्रफ का जिक्र नहीं किया लेकिन यह जाहिर हो रहा था कि वे मुशर्रफ के शासन में गैर सरकारी तरीकों से दोनों देशों के बीच बनी एक तरह की राजनीतिक सहमति का जिक्र कर रहे थे। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने मुशर्रफ के कार्यकाल में परदे के पीछे तय हुई राजनीतिक सहमतियों को लागू करने से मना कर दिया है। कुरैशी की टिप्पणियों से यह जाहिर है कि पाकिस्तान की सरकार इस इनकार पर दृढ़ है। भविष्य की ओर देखने वाली विश्वास कायम करने वाली बातचीत को रणनीतिक हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। इन उपायों में कराची में भारतीय वाणिज्य दूतावास और मुंबई में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास खोलने जैसा काम शामिल है। कराची में भारतीय वाणिज्य दूतावास 1994 में तब बंद कर दिया गया था जब बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थीं और भारत में वाणिज्य दूतावास खोलने की पाकिस्तान की मांग बहुत पुरानी है। इसके अलावा दोनों देशों की राजधानियों में पत्रकारों की संख्या बढ़ाया जाना और खुफिया व जांच एजेंसियों के बीच संपर्क तेज करना, अपराध की जांच और उन पर मुकदमा चलाए जाने के मामले में

> ***प्रेस कांफ्रेंस से यह आभास हो गया कि इनमें से किसी मुद्दे पर दोनों मंत्रियों की बात नहीं हुई, बल्कि बातचीत ज्यादातर उन मुद्दों पर केंद्रित थी जिनसे संबंध बिगड़ने की गुंजाइश थी। उन्हें अहसास हुआ कि प्रधानमंत्रियों ने जिन मुद्दों को विश्वास कायम करने के लिए आरंभिक कदम समझ था, उनके भी हल करने का समय अभी नहीं आया है। लगता है कि इस बैठक ने विश्वास कायम करने की प्रक्रिया शुरू करने के बजाय अविश्वास की मौजूदा दीवार को मजबूत ही किया है।***

पास्परिक कानूनी सहायता, व्यापार को प्रोत्साहन, भारत और अफगानिस्तान के बीच पारगमन व्यापार पर लगी पाकिस्तानी पाबंदी हटाया जाना, दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशन्स के डीजी स्तर पर महज हॉटलाइन तक सीमित संपर्क को बढ़ाना और दोनों के गृह या आंतरिक सुरक्षा मंत्रियों की कुछ अंतराल के बाद वार्ताएं जैसे कई कदम महत्वपूर्ण हैं। अगर इन उपायों पर सहमति बन जाए तो विश्वास कायम करने में जबरदस्त असर होगा। प्रेस कांफ्रेंस से यह आभास हो गया कि इनमें से किसी मुद्दे पर दोनों मंत्रियों की बात नहीं हुई, बल्कि बातचीत ज्यादातर उन मुद्दों पर केंद्रित थी जिनसे संबंध बिगड़ने की गुंजाइश थी।

उन्हें अहसास हुआ कि प्रधानमंत्रियों ने जिन मुद्दों को विश्वास कायम करने के लिए आरंभिक कदम समझ था, उनके भी हल करने का समय अभी नहीं आया है। लगता है कि इस बैठक ने विश्वास कायम करने की प्रक्रिया शुरू करने के बजाय अविश्वास की मौजूदा दीवार को मजबूत ही किया है। इससे स्पष्ट है कि बैठक के लिए किसी देश ने विधिवत तैयारी नहीं की थी। चूंकि हमारे प्रधानमंत्री विश्वास कायम करने के उपायों को काफी महत्व देते हैं इसलिए उम्मीद की जाती है कि कृष्णा के इस्लामाबाद दौरे से पहले उन्हें राजनीतिक आम सहमति के लिए विपक्षी नेताओं से बैठक की एक रणनीति तय कर लेनी चाहिए थी। इसके अलावा अंतरविभागीय आम राय के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक का कार्यक्रम भी बना लेना था। जाहिर है कि इस्लामाबाद में विश्वास कायम करने के प्रयासों से पहले दिल्ली में राजनीतिक और अंतरविभागीय आम राय कायम करने के लिए ऐसी कोई तैयारी नहीं की गई। सौभाग्य से इस्लामाबाद में जो वार्ता हुई, उसका सिलसिला टूटा नहीं है। बातचीत जारी रखने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री दिसंबर में भारत आएंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के उद्घाटन सत्र में गए तो प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और गिलानी की सितंबर में मुलाकात हो सकती है। उम्मीद है कि जुलाई के कड़ुवे अनुभव से सबक लेते हुए उन मुलाकातों में विश्वास कायम करने के नए तरीकों पर पहल भी हो जाए, लेकिन सितंबर से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विपक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ बैठकर यह तय करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को रणनीतिक और कार्यनीतिक तौर पर कैसे संभाला जाए। ■

(लेखक भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव रहे हैं और इस समय चेन्नई के इंस्टीट्यूट फॉर टॉपिकल स्टडीज के निदेशक हैं।)

(सौजन्यः हिन्दुस्तान)

~~~~~~~~~~☯☯☯~~~~~~~~~~

कांग्रेस आतंकवाद पर अफजली आंसू बहाना बंद करे : नकवी

Hkk रतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस आतंकवाद पर "अफजली आंसू" बहाना बन्द करे।

श्री नकवी ने 13 जुलाई को कहा कि कांग्रेस और उसकी सरकार की आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद पर कमजोर नीति और नीयत के चलते देश में आक्रोश है पर कांग्रेस आतंकवाद को कुचलने के बजाय उसे आक्सीजन देने में लगी है।

श्री नकवी ने कहा है कि कांग्रेस चाहती है कि उनकी नेता श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी की तरह देश की सभी राजनैतिक पार्टियॉं एवं नेता आतंकवाद पर चुप रहें, और इसीलिए आतंकवाद का विरोध करने वाले हर नेता के विरूद्ध कांग्रेस मोर्चा खोल देती है।

श्री नकवी ने कहा कि आतंकवादी अफजल या ओसामा बिन लादेन देश के मुसलमानों का आदर्श नहीं है पर कांग्रेस आतंकवाद को "हिन्दू–मुस्लिम" आतंकवाद बनाकर वास्तविक आतंकवाद से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है।

कांग्रेस से पांच सवाल

- क्यों कांग्रेस सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि आतंकवादी अफजल की फांसी से देश की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है?
- क्यों कांग्रेस आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद पर अपनी चौतरफा नाकामी पर "अफजली आंसू" बहा रही है?
- क्यों आतंकवाद को हिन्दू–मुस्लिम आतंकवाद बनाकर वास्तविक आतंकवाद से लोगों का ध्यान हटा रही है?
- क्यों कांग्रेस चाहती है कि आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद पर भाजपा भी श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरह चुप रहे?
- क्यों कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ उठी हर आवाज को मुसलमानों के खिलाफ उठी आवाज बताकर देश के करोड़ों मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति को गाली दे रही है?
~~~~~~~~~~

रेल दुर्घटनाएं और महंगाई सरकार के कुशासन का नमूना : राजीव प्रताप रूड़ी

यूपीए सरकार के शासन में भारतीय रेलवे के संचालन में बढ़ती अकुशलता दिल दहला देने वाली है। अब तो भयंकर दुर्घटनाओं में निर्दोष लोगों के जानें जाना इण्डियन रेलवे की नियमित विशेषता बन गया है। इस सम्बंध में मरने वालों के आंकड़े भयावह हैं 1 मई 2009 से अनेकों प्रमुख दुर्घटनाओं में लगभग 428 लोगों के प्राणों की आहुति हो चुकी है। सुरक्षा और सिक्युरिटी का विषय एकदम पीछे चला गया है जिससे रेलवे से सफर करने वाले आम आदमी की सुरक्षा और सिक्युरिटी समाप्त हो गई है। मालूम हुआ है कि रेलवे में 20000 से अधिक सुरक्षा पद खाली पड़ें हैं।

जहां एक तरफ रेलवे का आम यात्री उसकी घोर उपेक्षा को भुगत रहा है तो दूसरी तरफ रेलवे मंत्री पश्चिमी बंगाल राज की राजनीति में व्यस्त दिखाई पड़ती हैं। बार–बार की इन त्रासदीपूर्ण घटनाओं ने भी रेल मंत्री या प्रधानमंत्री या फिर यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की आत्मा को दहलाया नहीं है।

यूपीए के मंत्री एकदम स्वतंत्र तानाशाहों जैसा व्यवहार कर रहे हैं और लगता है कि प्रधानमंत्री इन मंत्रियों की घोर अनुशासनहीनता और अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण सेक्टरों की पूर्णतया बदइंतजामी पर अंकुश लगाने में एकदम असमर्थ हैं चाहे श्री शरद पवार की अध्यक्षता में चल रही कृषि और खाद्य मंत्रालय की बात हो, पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री श्री जयराम रमेश, दूरसंचार मंत्रालय के मंत्री श्री ए. राजा, रेलवे मंत्री सुश्री ममता बैनर्जी और अन्य बहुत से मंत्रालयों के मंत्रियों की बात करें तो देखेंगे कि ये सभी मंत्रीगण प्रधानमंत्री और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी से अलग कर स्वतंत्र रूप में कार्य कर रहे हैं। इन मंत्रियों की विशृंखलता और कुप्रबंध अत्यंत क्षोभकारी एवं चौपट करने का कार्य हैरत में डाल देता है। फिर भी, प्रधानमंत्री और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी देश और लोगों के प्रति इनकी पूर्ण उपेक्षा और निष्क्रियता के प्रति दमसाध चुप्पी बनाए हुए है। लगता है कि दुखद दुर्घटनाओं में लोगों की प्राणों की आहुति और लगातार बढ़ती महंगाई और खाद्य एवं कृषि क्षेत्र जो कि सड़ते टनों अनाज को देखते हुए की घोर कुप्रबंधता के कारण आम आदमी की मुसीबतों के कारण प्रधानमंत्री और श्रीमती गांधी पर जूं तक नहीं रेंग रही है।

जहां एक तरफ रेलवे का आम यात्री उसकी घोर उपेक्षा को भुगत रहा है तो दूसरी तरफ रेलवे मंत्री पश्चिमी बंगाल राज की राजनीति में व्यस्त दिखाई पड़ती हैं। बार–बार की इन त्रासदीपूर्ण घटनाओं ने भी रेल मंत्री या प्रधानमंत्री या फिर यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी की आत्मा को दहलाया नहीं है।

मंत्रीगण रोम के सम्राट नीरो की तरह बर्ताव कर रहे हैं और वे अपने मंत्रालयों के कामकाज की घोर उपेक्षा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनमें बेहद भ्रष्टाचार, प्रशासनिक उदासीनता और आम लोगों की चिंताओं और आवश्यकताओं की तरफ जरा भी ध्यान न देने की प्रवृत्ति बन गई है। ■

पृष्ठ 5 का शेष

समय यह बात भी स्मरणीय है कि कुछ आतंकवादी कैंपों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद कर दिया गया था।

किन्तु, लगता है कि यूपीए तो पाकिस्तान की बेकार की कोरी बातों और मांगों में आकर झुकने की खतरनाक नीति पर चल रही है कि किसी न किसी तरह से बातचीत का सिलसिला चलता रहे। भाजपा की मांग है कि यूपीए सरकार को 'किसी भी कीमत पर'' बातचीत की नीति छोड़ देनी चाहिए और भारत–विरोधी आतंकवादी तत्वों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद ही बातचीत करनी चाहिए।■

दुर्घटनाओं से रेलवे को दस सालों में ४५० करोड़ का नुकसान

j ल दुर्घटनाओं से रेलवे को हर साल औसतन 45 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। इस हिसाब से पिछले 10 साल में करीब 450 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद संरक्षा प्रणालियां लगाने को लेकर रेलवे की सुस्ती बरकरार है। जबकि यदि इन प्रणालियों पर एकमुश्त खर्च कर दुर्घटनाओं पर काबू पा लिया जाए तो अगले 20 साल में बचत के जरिए इस खर्च की खुद–ब–खुद भरपाई हो सकती है।

पिछले 10 साल की रेल दुर्घटनाओं के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान छोटी–बड़ी कुल मिलाकर 3,061 दुर्घटनाएं हुई। इन दुर्घटनाओं की वजह से किसी साल यह नुकसान 30 करोड़ रुपये रहा तो कभी साठ करोड़ रुपये। दुर्घटनाओं के कारण वर्ष 2006–07 में जहां 32 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, वहीं 2007–08 में 41 करोड़ रुपये का। जबकि वर्ष 2008–09 में 61 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। पिछले साल यानी 2009–10 में भी तकरीबन 40 करोड़ रुपये की रेल संपत्तियां दुर्घटनाओं की भेंट चढ़ गई। हालांकि रेलवे के मुताबिक, कुल दुर्घटनाओं का आंकड़ा साल–दर–साल गिर रहा है, लेकिन भयंकर दुर्घटनाओं और उनसे होने वाले नुकसान के आंकड़े कमोबेश बढ़े हैं।

ट्रेनों में भिड़ंत की सबसे ज्यादा 30 दुर्घटनाएं 2001–02 में हुई थीं। इसके बाद 2007–08 तक घटते–घटते इनकी संख्या आठ रह गई थी। अगले साल 2008–09 में फिर इनमें इजाफा हुआ और आंकड़ा 13 पर पहुंच गया। पटरी से ट्रेनों के उतरने की दुर्घटनाएं पहले के मुकाबले कम हुई हैं और इनकी संख्या 1999–2000 के 329 से घटकर 2008–09 में 85 पर आ गई। लेवल क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं में 2004–05 की गिरावट के बाद फिर इजाफा हुआ है। दस साल पहले 93 क्रॉसिंग दुर्घटनाएं हुई थीं। वर्ष 2004–05 में इनकी संख्या घटते–घटते 70 रह गई, लेकिन बाद के सालों में क्रमशः 75,79,77 और 69 क्रॉसिंग दुर्घटनाएं हुई हैं। ■

कैग की रिपोर्ट को रेलवे ने कूड़े में डाला

j ल हादसों को लेकर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह को रेल मंत्रालय के अफसरों ने कूड़ेदान में डाल दिया। पश्चिम बंगाल के साइंथिया में हुए रेल हादसे ने फिर से रेलवे की सिग्नलिंग प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कैग ने दो वर्ष पहले अपनी रिपोर्ट में रेलवे की सिग्नलिंग प्रणाली में कई खामियां गिनाईं थीं। रेल मंत्रालय ने कैग की सलाह पर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' तक पेश नहीं की।

रेल मंत्री ममता बनर्जी के कार्यकाल में छोटे–बड़े 11 रेल हादसे हो चुके हैं। हर वर्ष रेलगाडियों के टक्कर की करीब आधा दर्जन घटनाएं हो रही हैं। लगातार रेल हादसों के बावजूद रेलवे बोर्ड सिग्नल प्रणाली और दूरसंचार उपकरणों का आधुनिकीकरण तक नहीं कर पाया है। यह काम 2008 तक पूरा करना था।

इस साल 2 जनवरी को एक दिन में तीन रेल हादसे हुए। कुछ दिन बाद ही 16 जनवरी को टूंडला के पास फिर से दो गाड़ियों में भिड़ंत हो गई। 19 जुलाई की रात दो बजे साइंथिया में हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 69 तक पहुंच गई।

कैग की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेल के सिग्नलिंग एवं दूरसंचार विभाग को आधुनिक बनाया जाना था। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2003 में योजना बनाई थी। इसमें सिग्नलिंग एवं दूरसंचार खंड के लिए नई तकनीक अपनाने और पुरानी तकनीक का नवीनीकरण करना था। यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे छूट गई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में करीब 100 करोड़ रूपए खर्च करने के बावजूद एंटी कोलीजन डिवाइस (एसीडी) का उपयोग नहीं किया जा सका है। आरडीएसओ ने एसीडी को असंतोषजनक पाकर उसे क्लियरेंस ही नहीं दिया है। हद यह है कि दक्षिण मध्य एवं दक्षिण रेलवे में भी इसे लगाने के लिए 2.77 करोड़ रूपए की लागत से वर्ष 2003–04 में सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन वह धन भी एक तरह से बेकार गया। रेलवे ने कुछ योजनाएं बनाई और फिर बंद कर दी। इन पर खर्च हुए 9.63 करोड़ रूपए बर्बाद हो गए।

भारतीय रेल ने गेज परिवर्तन वाले खंड में सिग्नलिंग को सुधारने के लिए 20.11 करोड़ रूपए खर्च किए। इसमें भी कई खामियां पाई गईं। संचार चैनलों को अपने चैनलों में स्थानांतरित करने में भी रेलवे देरी करता रहा, इस कारण उसे बेवजह बीएसएनएल को 3.70 करोड़ रूपए का भुगतान करना पड़ा। ■

कांग्रेस, राजद तथा अन्य विपक्षी दलों का शर्मनाक हंगामा : रविशंकर प्रसाद

fcहार विधानसभा के दोनों सदनों में जो कुछ हुआ वह बेहद खेदजनक एवं निंदनीय है। टेलिविजन पर विपक्षी विधायकों के उपद्रवी व्यवहार ने हमारे लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है, जिसमें उनको विधानसभा के अध्यक्ष पर चप्पल फेंकते हुए, विधान परिषद के सभापति पर टूटा माइक फेंकते हुए और कांग्रेस की एमएलसी को फूलों के गमलों को तोड़ते–फोड़ते हुए दिखाया गया है। दोनों सदनों के अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री द्वारा नीत ट्रेज़री बेंच स्वयं उस तरीके से बहस कराये जाने के इच्छुक थे, जिस तरीके से प्रतिपक्ष चाहता था। मगर प्रतिपक्ष जानबूझकर बहस नहीं कराना चाहता था क्योंकि बहस के दौरान उसके कई काले कारनामे और राजद द्वारा कांग्रेस के समर्थन से किए गए भ्रष्टाचार के कई मामलों का भंडा फोड़ हो जाता। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट के तहत सीबीआई जांच से संबंधित उच्च न्यायालय के आदेश को आधार बनाकर प्रतिपक्ष ने सदन का कामकाज होने ही नहीं दिया। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश जिसके प्रति हम सभी सम्मान करते है, पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सीएजी रिपोर्ट 2002–07 की उस अवधि के बारे में है, जिसमें लगभग 42 महीने वे थे, जब कांग्रेस के समर्थन से राजद सत्तारूढ़ था। 11 महीने तक राष्ट्रपति शासन था, जिनके दौरान श्री बूटासिंह राज्यपाल थे। केवल 2 वर्ष की अवधि तक राजग सरकार सत्तारूढ़ रही। जदयू–भाजपा की मिलीजुली सरकार ने इस अवधि में अनुकरणीय विकास कार्य किया है, जिसमें विधि व्यवस्था पर काबू पाना शामिल है। अतः यदि बहस शुरू होती तो प्रतिपक्ष को बहुत अधिक सफाई देनी पड़ती।

विचाराधीन मुद्दा मूलतः लेखा समायोजन और व्यय के समाधान से सम्बंधित है। सांविधानिक व्यवस्था में अनुच्छेद 151 के तहत प्रस्तुत सीएजी रिपोर्ट को संसद के और राज्य लेखा के मामले में विधानमंडल के सम्मुख रखा जाता है। इसके बाद इसको लोक लेखा समिति को भेजा जाता है, जो इसकी राज्य सरकार के उत्तर के संदर्भ में जांच करती है और इसके पश्चात् कोई संशोधन आदि किए जाते हैं। तत्पश्चात् रिपोर्ट को सदन के सामने प्रस्तुत किया जाता है और परिचर्चा तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद यह फाइनल रिपोर्ट बन जाती है। जब तक ऐसी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक किसी परिचर्चा की अनुमति नहीं होती है। 2002–07 के वास्ते सीएजी की उपर्युक्त रिपोर्ट लोक लेखा समिति के विचारार्थ लंबित है, जिसके अध्यक्ष बिहार विधानसभा के प्रतिपक्षी विधायक है।

मगर, केवल इसलिए कि सीएजी ने कुछ लेखाविधि संबंधी विसंगति का उल्लेख किया था, जिसका समाधान किया जाना अथवा समायोजन किया जाना अपेक्षित है फिर जब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जाता है तब तक उसमें दुरूपयोग का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अन्यथा भारत सरकार का हजारों करोड़ रूपये का व्यय जो इसके बाद दिखाया जाता है सीधे तौर पर गबन बन जाता क्योंकि

गत 22 जुलाई, 2010 को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा जारी वक्तव्य

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इंगित किया है कि इन खर्चों के बारे में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। न केवल भारत सरकार में बल्कि कई राज्य सरकारों में भारी रकम का समाधान नहीं किया जाता है और |bstract Contingent Bills (IAC) के विरुद्ध Detailed Contingent bills (DC) प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। इन तथ्यों का स्वयं सीएजी की अलग–अलग रिपोर्टों में संकेत दिया गया है जैसाकि नीचे उल्लिखित किया जाता है।

भारत सरकार के बारे में कतिपय सीएजी रिपोर्ट

1. केन्द्र सरकार के 2008–09 (मार्च 2009 को समाप्त) वर्ष के वास्ते लेखों पर सीएजी की रिपोर्ट में विभिन्न विभागों में आउटस्टेंडिंग, यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट्स के वास्ते बार–बार निर्देश किए जाते हैं। इसका स्पष्टतः अर्थ है कि दिए गए अनुदान या व्यय हुए धन के विरूद्ध इसके यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट्स नहीं भेजे गए हैं। उक्त रिपोर्ट के Appendix-IX-D में पृष्ठ 205 पर भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग का आउटस्टेंडिंग यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट 200323.50 लाख अर्थात् 2003 करोड़ रूपए है इसी प्रकार परिवार कल्याण विभाग के मामले में उक्त राशि 978913.63 लाख अर्थात् लगभग 9789 करोड़ रुपए है
2. उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ 134 पर पैरा 9.28 में लिखा है कि ऑडिट स्क्रूटनी रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार के गृहमंत्रालय में तीन डिवीज़नों अर्थात् Border Management, Police Modernization और North-Eastern के बारे में 234.49 करोड़ रूपए का यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट सितंबर 2009 तक नहीं भेजा गया था। उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ 210 पर Appendix-IX-I पर विस्तृत चार्ट उल्लिखित है।
3. इससे पहले, वर्ष 2007–08 (मार्च 2008 को समाप्त वर्ष) हेतु केन्द्र सरकार के लेखों पर सीएजी की रिपोर्ट में पृष्ठ 241 पर Appendix-IX-E में पेडिंग यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट का चार्ट दिया हुआ है, जो उन अनुदानों के बारे में नहीं दिए गए थे, जिनको वितरित कर दिया गया था। इसका संबंध मानव संसाधन विकास विभाग (उच्च शिक्षा) से है, जिसके यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुए थे। जो यूटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट कनम थे उनकी रकम 112192.97 लाख अर्थात् लगभग 1121 करोड़ रूपए थी।

राज्यों के कुछ उदाहरण

4. **उत्तर प्रदेश राज्य -** उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार (संगत पृष्ठ 42 पैरा 2.4) वर्ष 2005–06, 2006–07 और 2007–08वर्षों के वास्ते समाधान न हुई भारी रकम, जो कुल 32456.02 करोड़ थी, का उल्लेख किया गया है।
5. vkUèkz izns'k jkT; & 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार के बारे में सीएजी की रिपोर्ट में पृष्ठ 37 पर पैरा 2. 3.14 में उल्लिखित है कि 29 विभागों के बारे में वर्ष 2007–08के वास्ते 55159.98 करोड़ रूपए के un-reconciled expenditure का उल्लेख है। उन विभागों का ब्यौरा सीएजी की उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ 208 पर Appendix 2.14 पर किया गया है। रिपोर्ट के पृष्ठ 137 के पैरा 2.3.13 में यह भी उल्लिखित है कि abstract contingency bills (AC) के रूप में निकाले गए 437.93 करोड़ रूपए का समायोजन नहीं किया गया है।
6. egkjk"Vª jkT; & महाराष्ट्र राज्य का मामला और अधिक दिलचस्प है। महाराष्ट्र राज्य की 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष हेतु सीएजी रिपोर्ट के पृष्ठ 46 पर पैरा 2.3.12 में उल्लिखित है कि मार्च 2008 तक abstract contingency bills (AC) के विरूद्ध 1246.78 करोड़ रूपए की भारी रकम के detailed contingent Bills (DC) की प्रस्तुति अभी लंबित है। आगे पृष्ठ 46 पर पैरा 2.4 में अप्रैल 2008 तक 3113.65 करोड़ रूपए के un-reconciled expenditure का उल्लेख है। उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ 223 और 224 पर Appendix 2.14 और 2.12 में ब्यौरे दिए गए हैं।
7. if'pe cxky jkT; & पश्चिम बंगाल सरकार की 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी की रिपोर्ट के पृष्ठ 39 और 40 के पैरा 2.6 में उल्लिखित है कि 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए 65.09 करोड़ रूपए और 31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 97 करोड़ रूपए की भारी राशि abstract contingency bills (AC) के विरूद्ध निकाली गई थी

उपर्युक्त केवल कुछ नमूने हैं। मगर यदि बिहार के प्रतिपक्षी दल, जिनमें राजद, कांग्रेस, लोजपा और वाम दल उल्लेखनीय है, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर राजग सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं तो उपर्युक्त स्पष्ट तथ्यों को देखते हुए केन्द्र सरकार और उपर्युक्त राज्य सरकारों के विरूद्ध भी सीबीआई जांच होनी चाहिए और उन्हें भी त्याग पत्र देना चाहिए। यदि बिहार के प्रतिपक्षी दल सोचते हैं कि ऐसा करके वे मतदाताओं को प्रभावित कर लेंगे – क्योंकि चुनाव निकट आ रहे हैं, तो वे भारी गलती पर हैं। जदयू – भाजपा सरकार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और लोग विकास का प्रभाव महसूस कर रहे हैं तथा वे वर्तमान सरकार को ही निश्चित तौर पर अपना जनमत प्रदान करेंगे चाहे उसके विरूद्ध कितना ही भी मिथ्या प्रचार क्यों न किया जाए।■

नए भाजपा प्रदेश प्रभारी, मोर्चा प्रभारी एवं अन्य प्रभारियों की नियुक्ति

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने 23 जुलाई को नए भाजपा प्रदेश प्रभारी, मोर्चा प्रभारी एवं अन्य प्रभारियों की नियुक्ति की। यह सूची निम्नलिखित है:–

प्रदेश प्रभारियों की सूची

Ø-	jkT;	iHkkfj;k dk uke
1.	मध्यप्रदेश	श्री अनंत कुमार
2.	छत्तीसगढ़	श्री जगतप्रकाश नड्डा
3.	कर्नाटक	श्री शांता कुमार
4.	हिमाचल प्रदेश	श्री कलराज मिश्र
5.	उत्तराखण्ड	श्री थावरचन्द गहलोत
6.	बिहार	श्री अनंत कुमार श्री धर्मेन्द्र प्रधान (सह प्रभारी)
7.	पंजाब	श्री यशवंत सिन्हा कैप्टन अभिमन्यु (सह प्रभारी)
8.	गुजरात	श्री बलबीर पुंज
9.	उत्तर प्रदेश	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर श्रीमती करुणा शुक्ला (सह प्रभारी) श्री राधामोहन सिंह (सह प्रभारी)
10.	राजस्थान	श्री कप्तान सिंह सोलंकी श्री किरीट सोमय्या
11.	हरियाणा	श्रीमती वसुंधरा राजे डॉ. हर्षवर्धन (सह प्रभारी)
12.	जम्मू और कश्मीर	श्री ओ.पी. कोहली श्री आर.पी. सिंह (सह प्रभारी)
13.	झारखंड	श्री भगतसिंह कोश्यारी (चुनाव प्रभारी) श्री हरेन्द्र प्रताप (प्रभारी)
14.	पश्चिम बंगाल	श्री चंदन मित्रा (प्रभारी) श्री सिद्धार्थनाथ सिंह (सह प्रभारी) श्री विनय कटियार (चुनाव प्रभारी)
15.	असम	श्री विजय गोयल (प्रभारी) श्रीमती किरण माहेश्वरी (सह प्रभारी) श्री वरूण गांधी (चुनाव प्रभारी)
16.	ओडिशा	श्री संतोष गंगवार
17.	अरूणाचल प्रदेश	श्रीमती बिजोय चक्रवर्ती
18.	मेघालय	श्री रमन डेका
19.	मणिपुर	श्री तापिर गाव
20.	मिजोरम	श्री रोमन डेका
21.	नगालैण्ड	श्री तापिर गांव
22.	केरल	श्री मुरलीधर राव श्री सदानंद गौडा (सह प्रभारी)
23.	तमिलनाडु	मे.ज. (से) बी.सी. खंडूरी (प्रभारी) श्री बंगारू लक्ष्मण (चुनाव प्रभारी)
24.	आंध्रप्रदेश	श्री पुरूषोत्तम रूपाला (प्रभारी) डॉ. वामन आचार्य (सह प्रभारी)
25.	महाराष्ट्र	श्री एम. वेंकैया नायडु डॉ. रमापति राम त्रिपाठी (सह प्रभारी)
26.	गोवा	श्रीमती आरती मेहरा
27.	पाण्डेचेरी	डॉ. लक्ष्मण
28.	अंडमान और निकोबार	श्री ला गणेशन
29.	लक्षद्वीप	श्री श्रीधरन पिल्लई
30.	दमन और द्वीप	डॉ. श्रीमती नजमा हेपतुल्ला
31.	दादर और नगर हवेली	डॉ. श्रीमती नजमा हेपतुल्ला
32.	दिल्ली	श्री एम. वेंकैया नायडु
33.	चण्डीगढ़	सुश्री सरोज पाण्डे
34.	सिक्किम	श्री इन्द्रसेन रेड्डी
35.	त्रिपुरा	श्री सुरेश पुजारी

ekpk çHkkfj;k vkj ekpk dh lph

Ø-	ekpk dk uke	iHkkfj;k dk uke
1.	efgyk ekpk	श्रीमती करूणा शुक्ला श्रीमती किरण घई (सह प्रभारी)
2.	;ok ekpk	श्री धर्मेन्द्र प्रधान श्री नवजोत सिंह सिद्धू (सह प्रभारी) सुश्री वाणी त्रिपाठी (सह प्रभारी)
3.	vulfpr ekpk	श्री थावरचन्द्र गेहलोत श्री अशोक प्रधान (सह प्रभारी)
4.	v-tutkfr ekpk	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
5.	fdlku ekpk	श्री सतपाल मलिक
6.	vYil[;d ekpk	श्री जे.के. जैन

जनता के लिए आंदोलन और संघर्ष हमारी पहचान : स्मृति ईरानी

Hkkरतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्मृति ईरानी ने 9 जुलाई को अपने अल्प भोपाल प्रवास के अवसर पर महिला मोर्चा की बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए लगातार संघर्ष किया है। जिससे पार्टी ने विशिष्ट पहचान बनायी है। महिला मोर्चा की बहनें जनहित में आंदोलन और संघर्ष करके अपनी पहचान बनायेंगी। महिला मोर्चा राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक प्रशिक्षण का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरंभ करेगा जिसमें गांव–गांव में महिला नेतृत्व को विकसित किया जायेगा। स्मृति ईरानी का भोपाल पहुंचने पर मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष नीता पटैरिया, सरिता देशपाण्डे, अर्चना चिटनीस, साधना सिंह, सीमा सिंह, महापौर कृष्णा गौर, बिलकिस जहां सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने पुष्प मालाओं से स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि स्मृति ईरानी के नेतृत्व में महिला मोर्चा प्रगति के नये क्षितिज पर पहुंचेगा। नीता पटैरिया ने कहा कि मध्यप्रदेश सौभाग्यशाली है जहां एक सप्ताह में स्मृति ईरानी दूसरी बार हमारे बीच में पहुंची है और हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।

स्मृति ईरानी ने कहा कि पार्टी संगठन में कार्यकर्ता ही हमारी प्रगति के सौपान है। जमीनी कार्यकर्ताओं के दम पर ही संगठन की विशाल अट्टालिका निर्भर है। कार्यकर्ताओं का स्थान बहुत ही सम्मानपूर्ण है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो बहनें संगठन की सिर्फ कार्यकर्ता मात्र है उन्हें हर दृष्टि से आगे लाया जायेगा और प्रोत्साहित किया जायेगा। महिला कार्यकर्ता बहनें अपनी क्षमता और नेतृत्व को विकसित करें। महिला नेतृत्व अपने आप में अपनी काबलियत साबित करेगा। हंसी के बीच स्मृति ईरानी ने कहा कि संख्या बल आंदोलनों और प्रदर्शनों के मौके पर सभी को महिला बहनों की याद आती है लेकिन जब टिकट का मौका आता है तो सभी ओर संकोच उभर आता है। आने वाले दिनों में महिलाएं प्रभावी नेतृत्व क्षमता का विकास करेगी और उनकी प्रधानता को कोई नहीं रोक पायेगा। महिलाओं को भरपूर टिकट दिलाने में उनकी क्षमता काम आयेगी। साथ ही समर्थन करने में हमको भी शक्ति मिलेगी। इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने भगीरथी बहन का विशेष उल्लेख किया जो एक हाथ से अपंग होने के बाद में भी बड़े उत्साह के साथ स्वागत समारोह में भाग ले रही थीं। ईरानी ने कहा कि हमें इस उत्साह से सबक लेना है और निरंतर जनसेवा में आगे बढ़ते रहना है। ■

---

vU; çHkkfj;kas dh lwph

1. ehfM;k — श्री रविशंकर प्रसाद
2. v-Hkk-dk;Øe o iwokZs — श्री मुख्तार अब्बास नकवी, श्री विजय गोयल, श्री किरीट सौमय्या, श्री भूपेन्द्र यादव
3. ÝMl vkQ chtsih — श्री पियूष गोयल
4. vkojlht ÝaMl vkQ chtsih — श्री बाळ आपटे, श्री अमित ठाकर (सह प्रभारी), श्री विजय जौली (सह प्रभारी)
5. lkLÑfrd izdk"B — श्रीमती हेमा मालिनी
6. f'k{kk izdk"B — प्रो. श्रीमती सुखदा पाण्डे
7. pquko 'kk/k vkSj fo'ys"k.k izdk"B — श्री अनिल माधव दवे
8. vkfFkZd ekeys — श्री प्रकाश जावडेकर
9. fof/k izdk"B — श्री सतपाल जैन ■

केरल के तालिबानीकरण पर श्वेत पत्र जारी हो : भाजपा

कोची के निकट एक अत्यंत घृणित घटना घटी, जिसमें मुस्लिम आतंकी ग्रुप ने एक ईसाई प्रोफेसर टी. जे. जोसेफ का हाथ काट दिया। भाजपा नेता श्री हरिन पाठक के नेतृत्व में गठित एक तथ्य जांच दल ने भाजपा अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी को अपनी रिपोर्ट पेश की। इस दल के अन्य सदस्यों में श्रीमती पिंकी आनंद, एडवोकेट एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा आल इण्डिया लीगल सेल की संयोजक, श्री बाला सुब्रह्मण्यम कामारसू, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया तथा डा. बिलफ्रेड एम. मोस्क्विटा, पूर्व मंत्री गोवा शामिल थे। श्री गडकरी को दी गई 19 जुलाई 2010 की रिपोर्ट इस प्रकार है:

प्रतिनिधिमण्डल का उद्देश्य:

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने उच्च स्तरीय शिष्टमंडल का गठन किया ताकि वह केरल का दौरा करे और केरल में प्रो. टी.जे. जोसेफ पर बर्बरता हमले की जांच करे; इसके पीछे के कारणों और अपराधियों का पता लगाए और समुचित कार्रवाई की सिफारिश करे।

घटना के तथ्य

4 जुलाई 2010, रविवार को मुवत्तुपुजा में कुछ अज्ञात लोगों ने एक प्राइवेट कॉलेज के लेक्चरार पर हमला किया और उनकी दांयी हथेली को काट डाला।

प्रो. टी.जे. जोसेफ को उनकी कार से खींच कर बाहर निकाला और आक्रमणकारियों ने तेजधार के हथियार से उनकी दांयी हथेली को काट डाला तथा उनकी बांयी टांग पर भी गहरी चोटें आयीं। उस समय वह अपने परिवार के साथ चर्च से घर लौट रहे थे, जिसमें उनकी बहन और 83 वर्षीय माता भी शामिल थी। उनकी बहन और माता पर भी हमला किया गया। 52 वर्षीय जोसेफ को कोची में एक प्राइवेट हस्पताल में ले जाया गया जहां उनकी काफी बड़ी सर्जरी हुई।

इदिक्की जिले में थोडुपुजा में न्यूमैन कॉलेज के मलयाली लेक्चरर श्री जोसेफ को पिछले अप्रैल में उनके द्वारा बी.कॉम द्वितीय वर्ष के लिए इंटरनल परीक्षा का एक प्रश्न पत्र सैट करने के बाद गिरफ्तार किया गया था क्योंकि मुस्लिम संगठनों ने यह कह कर विरोध किया था कि इससे उनकी मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंची है।

बाद में उन्हें कॉलेज से सस्पेंड (निलम्बित) कर दिया था, और कॉलेज अधिकारियों ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी थी।

यह गिरोह चाकुओं, तलवारों और अन्य हथियारों से लैस होकर एक गाडी में आया था। पहले तो इस गिरोह ने परिवार के सदस्यों को कार से बाहर निकाला और बाद में श्री जोसेफ की दांयी हथेली काट डाली। बांह से लेकर उनके दोनों हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गए। उनकी बहन के कथनानुसार आक्रमणकारी युवकजन थे। इससे पहले भी श्री जोसेफ पर तीन हमले हो चुके थे।

निकट के शहर थोडुपुजा में विभिन्न मुस्लिम ग्रुपों के विरोध के बाद लेक्चरर भागते रहे थे। शहर में झड़पें होने के बाद थोडुपुजा तनाव में रहा था और जिला अधिकारियों ने लोगों के जमघट होने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

राजनेताओं ने घटना की निंदा की। कड़े शब्दों में जारी एक वक्तव्य में इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा था कि दो गलतियों करने का मतलब उस गलती का सुधार होना नहीं हो जाता है और जो कुछ भी लेक्चरार ने किया वह अत्यंत भयावह है।

प्रतिनिधिमण्डल की कार्यवाही

श्री हरिन पाठक, सांसद, सुश्री पिंका आनंद, सीनियर एडवोकेट, माननीय सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया, राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य एवं आल इण्डिया लीगल सेल की संयोजक और श्री बालासुब्रह्मण्यम कामारसू, एडवोकेट, माननीय सुप्रीम कोर्ट आफ इण्डिया मिलकर 9.7.2010 को कोची के लिए रवाना हुए। प्रतिनिधिमण्डल के एक सदस्य डॉ. विलफ्रेड एम. मेस्क्विटा, पूर्व मंत्री गोवा सीधे गोवा से वहां पहुंचे।

अगले दिन, प्रतिनिधिमण्डल ने प्रदेशाध्यक्ष श्री बी. मुरलीधरजी, प्रवक्ता, श्री जार्ज कूरियन, प्रदेश अध्यक्षा, महिला मोर्चा श्रीमती शोभा सुरेन्द्रन के साथ मिलकर 11.30 बजे प्रो. टी.जे. जोसेफ

और डाक्टरों से भेंट करने के लिए मल्टीपल स्पेशिलिटी हस्पताल पहुंचे।

प्रतिनिधिमण्डल को बताया गया कि 2–3 दिन पूर्व कुछ मीडिया के व्यक्ति प्रो. टी.जे. जोसेफ से मिलने आए थे, जो अभी तक भी आईसीयू में हैं और उनका इंटरव्यू लिया था। डॉक्टरों ने प्रतिनिधिमण्डल को बताया कि मीडिया के व्यक्तियों के दौरे के बाद, उन्हें कुछ 'इंफेक्शन' हो गया है, हालांकि वह अब सामान्य हालत में हैं और चेतनावस्था में हैं परन्तु डॉक्टरों का परामर्श था कि इंफेक्शन होने के भय से बेहतर है कि आईसीयू में न जाया जाए, जिसे प्रतिनिधिमण्डल ने तुरंत स्वीकार कर लिया।

हस्पताल अधिकारियों ने इलाज करने वाले डॉक्टरों डा. जय कुमार और डा. शबीम और हस्पताल के डायरेक्टर्स को भी बुलाया। प्रोफेसर टी.जे. जोसेफ की बहन सुश्री स्टेला, जो एक सीनियर नन हैं और जो घटना के समय उनके साथ थीं, उस पर वहां मौजूद थीं। दोनों डॉक्टरों ने प्रतिनिधिमण्डल को बताया कि प्रो. टी.जे. जोसेफ को हस्पताल में बहुत ही गम्भीर हालत में लाया गया था। उनकी दांयी हथेली पूरी तरह से काट दी गई थी और उनको अन्य चोटें भी आयी थीं।

डॉ. जयकुमार के नेतृत्व में 7–8 डाक्टरों की टीम ने उनकी दांयी हाथ की हथेली को फिर से जोड़ा और आप्रेशन करने में 12 से 13 घण्टे लगे।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रो. टी.जे. जोसेफ चेतनावस्था और सामान्य हालत में हैं परन्तु अभी भी उनके दांये हाथ से काम करने के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।

इसी बीच प्रो. टी.जे. जोसेफ की बड़ी बहन सुश्री स्टेला ने 4.7.2010 को 8.30 बजे होने वाली घटना की पूरी जानकारी दी। पार्टी की ओर से प्रतिनिधिमण्डल ने प्रो. टी.जे. जोसेफ और परिवार के सदस्यों की शीघ्र स्वास्थ्य प्राप्त करने की कामना की और उन्हें कहा कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो, पूरी करने की कोशिश की जाएगी।

केरल में उग्रवादी गतिविधियां तेजी से बढ़ती ही जा रही है और सरकार की उग्रवादी ताकतों के खिलाफ संरक्षणवादी नीतियों के कारण तबाही मची हुई है। केरल एक सुन्दर, सभ्य, विधि पालक और प्रियजनों का राज्य है और भाजपा कभी भी इस शांतिप्रिय राज्य को तालिबानी गतिविधियों का अड्डा बनने नहीं देगी।

प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के एक काफी बड़े भाग ने हस्पताल में पूरी विजिट को कवर किया और, प्रतिनिधिमण्डल को बताया गया कि लोकल चैनलों ने हमारे प्रतिनिधिमण्डल के दौरे का प्रसारण किया है।

प्रतिनिधिमण्डल प्रो. टीजे जोसेफ के गृह–नगर मुवटुपुजा गया, जहां यह घटना हुई थी। यात्रा में लगभग एक घण्टा लगा। प्रतिनिधिमण्डल प्रो. टी.जे. जोसेफ के घर गया और उनकी पत्नी श्रीमती सेलोमी जोसेफ, उनके पुत्र जो एमबीए कर रहा है, श्री मिथुन टी जोसेफ; उनकी पुत्री सुश्री एनीजोसेफ (जो नर्सिंग का द्वितीय वर्ष का कोर्स कर रही है) और उनके ब्रदर–इन–लॉ से मिला।

उन सभी ने प्रतिनिधिमण्डल के दौरे और उनके हाल चाल जानने पर अपना आभार प्रदर्शन किया। उनके पुत्र और ब्रदर–इन–लॉ ने बताया कि इससे पहले उन्हें धमकियां मिलीं थी और कुछ शरारती तत्व घर तक भी पहुंचे। इस सम्बंध में उन्होंने 4.7.2010 को हुई घटना से पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, परन्तु स्थानीय पुलिस ने उनके परिवार और प्रो. टीजे जोसेफ की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया।

इसके बाद, प्रतिनिधिमण्डल घटना–स्थल पर गया जो प्रो. टीजे जोसेफ के घर से लगभग नजदीक ही था और फादर जार्ज पोत्ताकाल से मुलाकात की।

उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल का, प्रो. टी.जे. जोसेफ के परिवार और चर्च आने के लिए आभार प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल के साथ फोटो खिंचाने की इच्छा प्रगट की, जिसे हमने खुशी–खुशी स्वीकार किया और स्थानीय लोगों ने भी फोटो खींचे।

स्थानीय लोगों से चर्चा के दौरान प्रतिनिधिमण्डल को बताया गया कि 4.7.2010 की घटना के दिन ही हमलावरों की एक बड़ी भीड़ और उनके समर्थकों ने शाम को पुलिस स्टेशन का घेराव किया था परन्तु स्थानीय पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

अगले दिन 5.7.2010 को भारत बंद था। पापुलर फ्रंट के समर्थकों की लगभग 800 से 1000 भीड़ ने राष्ट्र–विरोधी और ईसाई–विरोधी नारे लगाते हुए मार्च किया था। परन्तु इसके बाद भी स्थानीय पुलिस ने इस गैर कानूनी रैली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके विपरीत पुलिस ने हमलावरों के समर्थन में पॉपुलर फ्रंट को रैली की अनुमति प्रदान की।

कोची से वापसी पर प्रतिनिधिमण्डल

ने आईजी सुश्री बी. संध्या, आईपीएस से बात की और केस की जांच के बारे में पूछताछ की। सुश्री संध्या ने बताया कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने माना कि ''इसके पीछे साजिश है।''

प्रतिनिधिमण्डल पौने पांच बजे कोची लौटा और एक प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित किया। प्रतिनिधिमण्डल ने हिंसा पर अपनी गहरी चिंता जताई और सीपीआई (एम) सरकार की अपार विफलता की निंदा की।

हमने कहा कि केरल में उग्रवादी गतिविधियां तेजी से बढ़ती ही जा रही है और सरकार की उग्रवादी ताकतों के खिलाफ संरक्षणवादी नीतियों के कारण तबाही मची हुई है। हमने यह भी कहा कि केरल एक सुन्दर, सभ्य, विधि पालक और प्रियजनों का राज्य है और भाजपा कभी भी इस शांतिप्रिय राज्य को तालिबानी गतिविधियों का अड्डा बनने नहीं देगी।

अपने दौरे में प्रतिनिधिमण्डल को लोगों, विभिन्न ग्रुपों और विभिन्न संगठनों एवं मीडिया से उग्रवादी गतिविधियों के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। प्रतिनिधिमण्डल ने राज्य के अपने नेताओं से परामर्श कर अपनी प्रेस कांफ्रेंस में मीडिया के सामने 3 प्रमुख मांगें रखीः

1. प्रो. टी. जे. जोसेफ पर हमले की घटना और केरल में हो रही तालिबानी मॉडल की अन्य गतिविधियों की जांच एनआईए (नेशनल इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी) द्वारा कराई जाए;
2. केरल की राज्य सरकार को राज्य में आतंकवादी/उग्रवादी गतिविधियों पर श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए;
3. राष्ट्र–विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट को एक गैर कानूनी संगठन के रूप में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

प्रेस कांफ्रेंस के बाद लगभग सायं 7 बजे प्रतिनिधिमण्डल ने स्टीफन अलतारा, केरल केथोलिक बिशप कौंसिल के प्रवक्ता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद, केरल केथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी की इन दो महत्वपूर्ण शख्सियतों– (1) फादर जॉर्ज पोटाकल और (2) फादर स्टीफन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूरा का पूरा ईसाई समुदाय ही बुरी तरह से विक्षुब्ध है और वह केरल में आतंकवादी ग्रुपों की गतिविधियों से गहरी पीड़ा और भय महसूस कर रहा है।

प्रतिनिधिमण्डल की टिप्पणी

1. पिछले लोकसभा चुनाव, 2009 में एनडीएफ ने, जिसका नाम एक राजनीतिज्ञ दल में बदल कर पॉपुलर फ्रंट पड़ गया है, कांग्रेस को समर्थन दिया था।
2. विधानसभा चुनाव में, पॉपुलर फ्रंट ने पूरे दिल से वर्तमान गृहमंत्री श्री कोडीगिरी बालाकृष्णन का समर्थन किया था।
3. गृहमंत्री सहित किसी एक मंत्री ने आजतक भी घायल प्रो. टी.जे. जोसेफ या उसके परिवार के सदस्यों के पास नहीं आया।
4. कोयम्बटूर विस्फोट का प्रमुख अभियुक्त श्री अब्दुल नासिर मदानी और जो अब तथाकथित हाल में हुए बंगलौर विस्फोट में भी शामिल है, आजकल कोची में है और कर्नाटक पुलिस एक–दो दिन में उसके खिलाफ वारण्ट जारी करने जा रही है।
5. प्रतिनिधिमण्डल को बताया गया कि कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दौरान तालिबान टेप प्राप्त हुए हैं जिनमें स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय कट्टर उग्रवादियों के बीच सम्बंध होने का पता चलता है।

निष्कर्ष

प्रतिनिधिमण्डल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि केरल की सिविल कम्युनिटी वर्तमान सीपीआई (एम) सरकार और कांग्रेस से बेहद नाराज और दुखी है। हमारा मानना है कि राज्य सरकार पापुलर फ्रंट के हमलावरों और समर्थकों के प्रति अत्यधिक उदार है। कारण स्पष्ट हैं क्योंकि प्रो. टी.जे. जोसेफ के परिवार द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस ने हमलावरों और पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

ऐसे पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि यह हमला पूर्व–नियोजित साजिश का नतीजा था जिसमें स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादियों के साथ गहरे सम्बंधों का पता चलता है।

प्रतिनिधिमण्डल की सिफारिशें

1. पिछले लोकसभा चुनाव, 2009 में एनडीएफ ने, जिसका नाम एक राजनीतिज्ञ दल में बदल कर पापुलर फ्रंट पड़ गया है, कांग्रेस को समर्थन दिया था।
2. विधानसभा चुनाव में, पापुलर फ्रंट ने पूरे दिल से वर्तमान गृहमंत्री श्री कोडीगिरी बालाकृष्णन का समर्थन किया था।

1. प्रो. टी. जे. जोसेफ पर हमले की घटना और केरल में हो रही तालिबान मॉडल की अन्य गतिविधियों की जांच एनआईए (नेशनल इंवेस्टिगेटिंग एजेंसी) द्वारा कराई जाए;
2. केरल की राज्य सरकार को राज्य में आतंकवादी/उग्रवादी गतिविधियों पर श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए;
3. राष्ट्र–विरोधी गतिविधियां चलाने के लिए पापुलर फ्रंट को एक गैर कानूनी संगठन के रूप में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ■

हरियाणा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा

जलसंरक्षण के पुराने तरीकों को अमल में लाने की जरूरत

Hkk जपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गड़करी के निर्देश पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सर्वश्री नवजोत सिंह सिद्धू व कैप्टन अभिमन्यु ने 11 जुलाई, रविवार को हरियाणा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया।

दिल्ली से पानीपत, करनाल होते हुए दोपहर 12 बजे कुरूक्षेत्र पहुंच कर प्रैस वार्ता की व मीडियाकर्मियों के साथ ही कुरूक्षेत्र नगर की बाढ़ग्रस्त कॉलोनी कीर्ति नगर व दीदार नगर में दौरा किया। तत्पश्चात जिले के मुकीमपुर, सिंह पुरा, भैंसी माजरा, सारसा व नानकपुरा गांवों में पहुंच कर ग्रामीणों से चर्चा करते हुए बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। कुरूक्षेत्र के बाद नजदीक ही बसे शहर पेहवा व ग्रामीण क्षेत्रों (देवीपुर झील, बढमाजरा, इस्माईलाबाद, सैनी माजरा) का भी जायजा लिया।

कुरूक्षेत्र व पेहवा के बाद अम्बाला में आंगड़ी नदी के बांध का सर्वेक्षण करने के बाद प्रैस वार्ता करने के बाद शहर की सबसे बड़ी कपड़ा मार्किट ''भगत सिंह कपड़ा मार्किट'' व ''राय मार्किट'' में व्यापारियों के हुए नुकसान की जानकारी ली तथा उन्हें सांत्वना देते हुए उचित मुआवजे की मांग उठाने का भरोसा दिया।

बाढ़ से नुकसान

1. कुरूक्षेत्र, कैथल, अम्बाला, फतेहाबाद, सिरसा में 2 लाख 85 हजार 700 हैक्टेयर भूमि पर धान एवं अन्य खड़ी फसल पूरी बर्बाद हो गयी।
2. हरियाणा भर में 150 से ज्यादा गांव बाढ़ ग्रस्त हो चुके हैं।
3. अगले 2 महीने तक पानी खेतों में खड़ा रहने की सम्भावना।
4. बाढ़ में कुल 16,900 नलकूप क्षतिग्रस्त हुए हैं।
5. बागवानी का 20,000 हैक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ है।
6. कई गांवों में बिजली पेयजल व्यवस्था ठप्प है जिसके कारण आमजन को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
7. पानी में डूबी हुई फसल से कोई पैदावार होने की उम्मीद नहीं है, जिसके कारण किसान को 25,000 रू प्रति एकड़ नुकसान हुआ है।
8. जो मजदूर बुआई, रखवाली, बटाई, कटाई आदि पर मजदूरी लेकर अपना पेट भरते हैं उन्हें भविष्य में इस तरह की कोई कमाई नजर नहीं आ रही है।
9. क्षेत्र के हजारों मकानों में दरार आने से नुकसान हुआ है।
10. बाढ़ राहत कार्य तेजी से न होने के कारण कई तरह की बीमारियों का प्रकोप बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बढ़ रहा है।
11. क्षेत्र के सैकड़ों मकान व प्रतिष्ठान ध्वस्त हो गये हैं।
12. कई गांव जिनसे संपर्क टूट गया है, वहां तक सरकारी राहत समय पर नहीं पहुंच पा रही है जिसके कारण लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा है।
13. कई गांवों में भोजन तक नहीं पक पाया, भूखे मरने की नौबत हैं।
14. कई गांवों के लोग पीने के पानी के लिए त्राहि–त्राहि कर रहे हैं।
15. लोग तो छतों पर चढ़कर अपना बचाव कर रहे हैं, परन्तु पशु पानी में ही खड़े हैं।
16. पशुओं के चारे का लगभग 26,600 हैक्टेयर क्षेत्र नष्ट हो गया है, चारा उपलब्ध नहीं हो रहा है जिसके कारण पशु भूख से मर रहे हैं।
17. अम्बाला कैंट और शहर के बाजारों में 3–4 फुट पानी 3–4 दिन भरा रहा, जिसके कारण से 2000 छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ।
18. व्यापारियों का औसतन 5 लाख रूपए का दुकान में रखा सामान पूरी तरह से खराब होकर नष्ट हो गया।
19. गोदामों में खुले में अनाज रखा गया था, जो पूरी तरह खराब हो गया और खाने के लायक नहीं रहा है।
20. ग्रामीणों का तेजी से पलायन शुरू हो चुका है।

बाढ़ के प्रमुख कारण

1. एसवाईएल नहर की नींव सन 1981 में रखी गई थी। इसमें नांगल डैम से ही पानी लेकर हरियाणा के आखिरी छोर तक पहुंचाना था तब इसे 7200 क्यूसिक की क्षमता का बनाया गया था, लेकिन जब पानी नहीं आया तो सरकार व प्रशासन और नहरी महकता इसे भूल बैठा। हिमाचल और पंजाब के ऊपरी इलाकों से नहर में पानी हर वर्ष आता है। उपेक्षा के चलते इसकी क्षमता 3000 क्यूसिक से भी कम हो गई और अब अचानक इसमें 7000 क्यूसिक पानी आ गया।
2. हरियाणा की एसवाईएल, हांसी बुटाना, टांगड़ी नदी, घग्गर आदि नहरें पंजाब की नहरों से जुड़ी हुई है जिनमें हिमाचल व पंजाब में

अधिक वर्षा होने पर पानी छोड़ा जाता है।

3. सरकार ने बाढ़ से बचाव का इंतजाम यमुना नदी से किया, जबकि एसवाईएल और हांसी–बुटाना नहरों ने कई जिलों को डुबा दिया।
4. सिंचाई विभाग ने इस साल अब तक बाढ़ बचाव कार्यों पर मिले फंड 75 करोड़ रूपये में से मात्र 23 करोड़ रूपये ही खर्च किये हैं।
5. सरकार यह कहते नहीं थकती थी कि 400 करोड़ की लागत से हांसी–बुटाना लिंक नहर का निर्माण किया गया है, जो राज्य के करीब डेढ़ दर्जन जिलों को पानी देगी। ऐसे में तेज बारिश और पानी के अधिक बहाव से इस नहर का जगह–जगह से टूट जाना कई तरह के सवाल खड़ा करता है। इस नहर का निर्माण साल भर पहले ही किया गया है।
6. हरियाणा में Flood Drain, का पूरा नेटवर्क है, जिसका ठीक से रखरखाव नहीं किया जा रहा है और बाढ़ के पानी को इस नेटवर्क में छोड़ा ही नहीं गया।
7. एसवाईएल की मरम्मत के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं है, ना ही इसकी मरम्मत की गई है।
8. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी कुछ क्षेत्र विशेष को बाढ़ से बचाने के लिए लिये, यहां पर हर वर्ष इन नहरों के किनारे जानबूझकर तोड़ते हैं, जिससे फसलों का भारी नुकसान होता है।

समिति की मांगें

1. जिस भूमि पर नुकसान हुआ है उस पर किसानों को 25000 रूपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जायें।
2. जिन घरों व प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा है उन्हें उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाये।
3. जिन छोटे व्यापारियों को पानी भरा रहने से लाखों का नुकसान हुआ है, उनके नुकसान की भरपाई की जायें।
4. खेतीहारी गरीब मजदूरों को भी अलग से 5000 रूपए प्रति परिवार मुआवजा मिलना चाहिए।
5. बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए प्रशासन की ओर से कोई सुनियोजित कार्यवाही नहीं की जा रही है और ना ही सरकार ने बाढ़ से पूर्ण राहत के लिए कोई निर्णय लिया है अतः सरकार व प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की राहत हेतु ठोस कदम उठायें।
6. नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए टीम गठित की जायें जिसमें स्थानीय जन प्रतिनिधि (पटवारी, सरपंच या पार्षद) मौजूद हों।
7. जिन अधिकारियों के कारण इतना नुकसान हुआ, उनकी जिम्मेदारी तय की जाये व उन पर उचित कार्यवाही की जाये।
8. बाढ़ राहत के लिए करोड़ों का बजट मिलता है उस पैसे का क्या हुआ? इसका खुलासा किया जाये।
9. पानी की निकासी के लिए Flood Drains की समुचित मरम्मत करने के कार्य जल्द से जल्द पूर्ण किये जायें।

उपाय

1. अगर सही योजना–नीति से जल नियोजन लागू किया जाता तो यही पानी वरदान साबित हो सकता था, जो अभिशाप बन गया।
2. क्षमता से अधिक जो पानी आया था, अगर वह Flood Drain, के माध्यम से तालाब झीलों, बावड़ी, कुओं जैसें भिण्डावास, दमदमा, सुल्तानपुर, चिल्ली आदि जो अभी भी सूखी है, में पहुंचाया जाता तो वरदान साबित होता। परन्तु वहां पहुंचाने की व्यवस्था तो दूर जो व्यवस्थायें या नाले हैं उनकी मरम्मत भी नहीं की गई।
3. नीति और नीयत का अभाव।
4. सरकार, प्रशासन की अकर्मण्यता व उदासीनता के कारण ऐसी विपदाओं का सामना करना पड़ रहा है।
5. हरियाणा में भू–जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, इसके निवारण के लिए कूए खोदकर, बाढ़ का पानी जमीन में उतार कर जलसंग्रह करके इसे सुधारा जा सकता है।
6. पानी का प्राकृतिक बहाव अब अवरोधों के कारण से बिगड़ गया है। इन अवरोधों को समाप्त किया जायें और पानी के बहाव को बांधकर नियंत्रित कर सूखे इलाकों की तरफ से ले जाया जाये।
7. जल संवर्धन के पुराने तरीके जैसे की कुएं, तालाब, बावड़ी, झील इत्यादि की खुदाई, नियमित सफाई और बाढ़ के पानी को इन तक पहुंचाने की योजना एवं नेटवर्क की आवश्यकता है। जिससे अधिक पानी आने पर दक्षिण हरियाणा जहां गंभीर जल संकट है, वहां बाढ़ के पानी को स्टोर किया जा सके और अन्य क्षेत्रों को बाढ़ से बचाया जा सके। ■

महंगाई की मार से आम आदमी परेशान : विजय गोयल

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

> ***अब देश के लोगों ने महसूस कर लिया है कि मूल्यवृद्धि कांग्रेस की जन–विरोधी नीतियों का ही परिणाम है – चाहे वह आयात–निर्यात हो, राजकोषीय मामला हो, खाद्य स्टॉक का प्रबंधन हो तथा वायदा बाजार आदि के बारे में लिए गए निर्णय हों। थोक मूल्य सूचकांक दो अंकों में प्रवेश कर रहा है, खाद्य पदार्थों के मूल्य लगभग 16 प्रतिशत ऊंचे हो रहे हैं।***

कांग्रेस – नीत यूपीए सरकार की गलत आर्थिक नीतियों, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप आज महंगाई सारी सीमाओं को पार कर गई है। भाजपा इस यूपीए सरकार की जन–विरोधी नीतियों के विरूद्ध सड़क से लेकर संसद तक अपना विरोध जारी रखेगी। इसी क्रम में बेलगाम बढ़ती महंगाई के विरूद्ध आम जनता में जागरूकता पैदा करने व केन्द्र सरकार द्वारा पैट्रोल, डीज़ल, कैरोसीन व रसोई गैस की बढ़ी कीमतों को वापस लेने के उद्देश्य से भाजपा ने देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत लगभग 10 करोड़ लोगों ने महंगाई विरोधी हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर कर अपना विरोध प्रदर्शित किया है। दिनांक 29 जुलाई, 2010 को यह देशव्यापी हस्ताक्षरित ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सौंपा जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, भाजपा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, भाजपा के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, एवं सभी सांसद सम्मिलित होंगे।

जहां भारत के लोग बढ़ती कीमतों के नीचे सिसक रहे हैं, वहीं आम आदमी पर कांग्रेस का हमला बदस्तूर जारी है। लोगों के घावों पर मरहम लगाने की बजाय कांग्रेस उन पर नमक छिड़कने पर तुली हुई है। पहले, केन्द्रीय बजट और फिर दिल्ली स्टेट के बजट ने लोगों की कमर तोड़ दी। केन्द्रीय बजट के द्वारा पैट्रोल, डीज़ल, उर्वरकों के मूल्य बढ़ाए गए, जिनका मुद्रास्फीति पर कुप्रभाव पड़ा और अन्य करों में भी वृद्धि हो गई। साथ ही सेवा कर ने भी आम आदमी पर भारी बोझ डाल दिया। फिर जून माह में पैट्रोल डीज़ल कैरोसिन ऑयल एवं रसोई गैस के दामों में फिर से वृद्धि की गई परिणामस्वरूप महंगाई थमने के बजाय बेहताशा बढ़ती ही जा रही है। आश्चर्य तो यह है कि एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ केंद्र में बैठी सरकार के मंत्री चुप्पी साधे बैठे है। देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री अनुभवी वित्त मंत्री भविष्यवाणियां कर रहें हैं। कुछ माह में महंगाई कम होने की बात की जा रही है कांग्रेसनीत सरकार आशवासन ही देती रही है कि मंहगाई कम होगी। लेकिन मंहगाई रूकने का नाम ही नही ले रही है। कालाबाजारी, स्टॉककिस्ट बढ़ रही हैं। सरकार की नीतियाँ असफल साबित हो रही है। यही नहीं, सरकार जो नीतियां बना रही है, उससे मंहगाई और भी बढ़ती जा रही है।

अब देश के लोगों ने महसूस कर लिया है कि मूल्यवृद्धि कांग्रेस की जन–विरोधी नीतियों का ही परिणाम है – चाहे वह आयात–निर्यात हो, राजकोषीय मामला हो, खाद्य स्टॉक का प्रबंधन हो तथा वायदा बाजार आदि के बारे में लिए गए निर्णय हों। थोक मूल्य सूचकांक दो अंकों में प्रवेश कर रहा है, खाद्य पदार्थों के मूल्य लगभग 16 प्रतिशत ऊंचे हो रहे हैं।

कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा–पत्र में यह वायदा किया था कि महज सौ दिन में ही हम महंगाई कम कर देंगे। वह महंगाई, जिसकी मार आम जनता यूपीए–I के शासनकाल के अंतिम वर्षों में झेल रही थी। यूपीए–II के शासन के सौ दिन पूरे हुए और महंगाई कम होने की बजाय कई गुना बढ़ गई। एक वर्ष पूरे होने के पश्चात् भी महंगाई की रफ्तार घटने के बजाय बढ़ती ही चली गई।

आश्चर्य है – एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के शासनकाल में मंहगाई बेलगाम बढ रही है और प्रधानमंत्री महोदय इस विषय पर कुछ भी कर पाने में असफल साबित हो रहे हैं।

भाजपा मांग करती है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश की जनता को बताएं कि आखिर इस बढती हुई मंहगाई को रोकने के लिए प्रधानमंत्री व सरकार कौन कौन से कदम उठा रही हैं या यह सब आश्वासन महज एक भुलावा है। ■

पेट भरने का कठिन सवाल

& nfoanj 'kek

bससे अधिक निराशाजनक कुछ नहीं हो सकता कि स्वतंत्रता के 63 साल के बाद भी सोनिया गांधी–नीत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ने देश की भूखी जनता का पेट भरने से हाथ खड़े कर दिए हैं। इसका सीधा सा फरमान है–भूखे को भूखे ही रहना होगा। एक ऐसे देश में जहां विश्व की सबसे अधिक आबादी भुखमरी का शिकार है और जहां कुल बच्चों की आधी संख्या कुपोषित है, मैं सोनिया गांधी से उम्मीद कर रहा था कि वह भूख को इतिहास बनाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा करेंगी। किंतु जैसाकि अखबारों में छपी खबरों को पढ़कर लगता है कि एनएसी की अनुशंसाएं करोड़ों भूखों और कुपोषित लोगों के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव नहीं ला पाएंगी। सोनिया गांधी ने शायद प्रयास तो किया किंतु एनएसी टीम ने उनके उत्साह पर पानी फेर दिया।

देश के सर्वाधिक गरीब 2000 विकास खंडों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए प्रतिमाह 35 किलोग्राम खाद्यान्न तीन रुपये किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराने और गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले परिवारों के लिए 25 किलोग्राम खाद्यान्न मुहैया कराने को सकल खाद्यान्न अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करना समझदारी भरा कदम नहीं है। मैं कभी भी सकल खाद्य अधिकार का पक्षधर नहीं रहा हूं। मध्य वर्ग खुद का पेट भरने में सक्षम है। अगर वह चमचमाती कारें और महंगी उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकता है तो फिर खाद्यान्न जरूरतें पूरी क्यों नहीं कर सकता। चुनौती तो भूखे का पेट भरने की है। आईसीएमआर के मापदंड़ों के अनुसार, प्रत्येक शारीरिक रूप से सक्षम वयस्क के लिए प्रतिमाह कम से कम 14 किलोग्राम खाद्यान्न जरूरी होता है। अगर एक परिवार में औसतन पांच व्यक्ति मान लिए जाएं तो प्रतिमाह 70 किलोग्राम खाद्यान्न की

जरूरत पड़ेगी। केवल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराकर हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भूखे हमेशा के लिए भुखमरी से उबर न पाएं। वैसे भी, इतना तो उन्हें पहले भी मिल ही रहा था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का उद्देश्य मात्र इतना है कि जितना खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहले से ही दिया जा रहा था, उसे वैधानिक दर्जा दिया जा सके। अधिक खाद्यान्न आवंटन करने के विरोध में यह दलील दी गई कि देश में औसतन पांच करोड़ टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद होती है। अगर प्रति परिवार 35 किलोग्राम से अधिक का वादा किया जाता है तो सरकार इस अधिकार की पूर्ति में विफल हो जाएगी। मेरे हिसाब से यह महज क्षमायाचना ही है। यह ठीक है कि भारत में वर्षों से खाद्यान्न उत्पादन स्थिर है किंतु इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि यहां उचित भंडारण के अभाव में खाद्यान्न का बड़ा भाग सड़ जाता है। इसके अलावा, यह भी सही है कि अगर किसानों को आकर्षक मूल्य दिया जाए तो वे उत्पादन

> ***एक ऐसे देश में जहां विश्व की सबसे अधिक आबादी भुखमरी का शिकार है और जहां कुल बच्चों की आधी संख्या कुपोषित है, मैं सोनिया गांधी से उम्मीद कर रहा था कि वह भूख को इतिहास बनाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा करेंगी। किंतु जैसाकि अखबारों में छपी खबरों को पढ़कर लगता है कि एनएसी की अनुशंसाएं करोड़ों भूखों और कुपोषित लोगों के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव नहीं ला पाएंगी।***

दोगुना कर सकते हैं। इस संदर्भ में चीन का उदाहरण उल्लेखनीय है। इसकी आबादी भारत से करीब 20 करोड़ अधिक है। भारत में कुल 23 करोड़ टन खाद्यान्न की तुलना में चीन में करीब 50 करोड़ टन का उत्पादन होता है। दोगुने खाद्यान्न उत्पादन के बावजूद चीन घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारी मात्रा में खाद्यान्न का आयात करता है। भारत के विपरीत जो अपने देशवासियों के भूखे रहने पर भी खाद्यान्न का निर्यात करता है, चीन खाद्यान्न और कृषि उपजों का विश्व का प्रमुख आयातक देश बन गया है। भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता प्रतिदिन 500 ग्राम से भी कम है। दूसरी तरफ, चीन में यह आंकड़ा तीन किलोग्राम से भी अधिक है।

यह आश्चर्यजनक है कि भारत भूखी जनता के बल पर उच्च संवृद्धि हासिल करना चाहता है, जबकि चीन एक स्वस्थ और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। वह जानता है कि जनता का पेट भरे रहना राजनीतिक आवश्यकता ही नहीं, सामाजिक और आर्थिक सुदृढ़ता के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा विद्रोह से बचाव की पहली शर्त है। इसलिए दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए कृषि के कायाकल्प की आवश्यकता है। मैंने सोनिया गांधी से यह भी अपेक्षा की थी कि वह योजना आयोग और खाद्य एवं कृषि मंत्रालय की सलाह पर ध्यान नहीं देंगी और देश से भुखमरी मिटाने की कारगर योजना पेश करेंगी, जिसमें टिकाऊ कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित देने के उपाय भी शामिल हों। इसके अलावा कृषि अर्थव्यवस्था को लाभकारी बनाने की भी अपेक्षा की जा रही थी। इसके तहत व्यापार और विकास नीतियों के पुनर्निर्धारण और सब्सिडी पर आधारित सस्ते विदेशी कृषि उत्पादों के आयात के दरवाजे बंद करने जैसे उपाय जरूरी हैं। यही नहीं, कॉर्पोरेट कृषि को बढ़ावा देने के बजाय छोटी जोतों को लाभकारी व पर्यावरण के अनुकूल बनाने के प्रयास होने चाहिए थे।

आईसीएमआर के मापदंडों के अनुसार, प्रत्येक शारीरिक रूप से सक्षम वयस्क के लिए प्रतिमाह कम से कम 14 किलोग्राम खाद्यान्न जरूरी होता है। अगर एक परिवार में औसतन पांच व्यक्ति मान लिए जाएं तो प्रतिमाह 70 किलोग्राम खाद्यान्न की जरूरत पड़ेगी। केवल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराकर हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भूखे हमेशा के लिए भुखमरी से उबर न पाएं।

किसी भी सफल खाद्य सुरक्षा पहल की कुंजी क्षेत्रीय उत्पादन और क्षेत्रीय सरकारी खरीद पर टिकी होती है। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उचित नीतियां और योजनाएं बनाई जानी चाहिए थीं, जो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अधिकार में कटौती करने के साथ–साथ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय का दायरा विस्तृत करतीं। इसके लिए समग्र आर्थिक नीति बदलाव की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि भूमि पर उद्योग धंधे नहीं लगाए जाएंगे तथा जीएम फसलों के माध्यम से किसानों को बर्बाद नहीं जाएगा। यह देखते हुए कि उत्पादन बढ़ाना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आता, इस संबंध में जिक्र मात्र से कोई लाभ नहीं होगा। अगर अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर नए खाद्य आयुक्त और राज्य स्तर पर राज्य आयुक्तों के पदों का गठन मात्र है तो देश के भूखे लोगों का पेट भरने के मूल उद्देश्य का लोप हो जाएगा।

यद्यपि एनएफएस, ने सामाजिक वंचित की नई श्रेणी ईजाद की है, किंतु यह सुनिश्चित नहीं किया है कि इसे क्रियान्वित कैसे किया जाएगा। इसके विपरीत, इसमें अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की काफी गुंजाइश छोड़ दी गई है। खाद्य सुरक्षा का बेहतर विकल्प यह था कि गरीबी से नीचे रहने वालों की संख्या 55 फीसदी कर दी जाती ताकि इस रेखा के किनारे पर रहने वाले लोग भी इसके दायरे में आ जाते। यह हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बहुआयामी ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के आकलनों के अनुरूप भी होता। देश के आठ राज्य–बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सर्वाधिक गरीब 26 अफ्रीकी देशों से भी अधिक गरीब हैं। 88 देशों के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है। भुखमरी और गरीबी की रैंकिंग में भारत के अफ्रीकी राष्ट्रों से भी नीचे रहने को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधिकांश अफ्रीकी राष्ट्रों में अशांति है और वहां अस्थिर सरकार हैं। अगर उन अफ्रीकी राष्ट्रों में भारत जैसी स्थिर सरकार होती, तो निश्चित रूप से भारत गरीबी और भुखमरी सूचकांक की तली में होता। मैं नहीं जानता कि हम भारतवासी कब तक भुखमरी और कुपोषण को लेकर उदासीन बने रहेंगे। (लेखक कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं) ■

वंचित जनजातियों की तरक्की में राह बनना होगा

& Hkjrpæ uk;d

V राजकता को ही सरल भाषा में जंगल कानून कहा जाता है। लेकिन यह एक हकीकत है कि जंगल कानून को तोड़कर देश और मध्यप्रदेश के जनजाति समुदाय और स्वतंत्रता प्रेमी जनता ने ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी थी। माना जाता है कि स्वतंत्रता प्रेमी वनवासियों की उत्कट आजादी की लालसा का दमन करने के लिए ही अंग्रेजों ने जंगल कानून बनाकर वनवासियों को उनकी बसाहटों में कैद कर दिया था। बाद में वे जंगल के मजदूर बनकर रह गये। वनोपज का अधिकार भी उनके हाथ से छिन गया। आजादी के बाद वनवासियों, आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सिर्फ उतने प्रयास किये गये जितने में माना गया कि उनका सांस्कृतिक स्वरूप अप्रभावित रहे।

जंगली फूलों से मदिरा बनाकर सेवन करना उनके परंपरागत अधिकार में शामिल कर दिया गया। इससे उनमें आगे बढ़ने के बजाय परम संतोष में डूबे रहने की आदत बन गयी। सामाजिक, आर्थिक तरक्की की दिशा में वनवासी बढ़ पाने के बजाय शोषकों के शोषण का साफ्ट टारगेट बनकर रह गये। मध्यप्रदेश में वनवासियों को उनके वनभूमि पर कब्जे वाली वनभूमि पर अधिकार दिलाने की पहल साठ के दशक में तत्कालीन भारतीय जनसंघ के आंदोलन से शुरु हुई।

प्रदेश में लंबी लड़ाई के बाद संविद सरकार बनने पर प्रयासों में कुछ गति मिली। लेकिन इसमें तीव्रता लाने के प्रयास अधिक कारगर नहीं हो पाये। बाद में मुरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में जब केन्द्र में सरकार बनी, तब गंभीरतापूर्वक विचार हुआ। लेकिन सरकार अल्पजीवी थी।

नब्बे के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब एनडीए सरकार बनी तो मंडला प्रवास पर पहुंचे अटल बिहारी वाजपेयी ने वनभूमि पर परंपरागत अतिक्रमण के मामले में वनवासियों के उत्पीड़न को नजदीक से देखा और केन्द्र में वनभूमि पर वनवासियों, परंपरागत रहवासियों के अधिकार को मान्यता दिये जाने का ऐलान किया। विधेयक बनने की प्रक्रिया जब आरंभ हुई तो कानूनी दांवपेंच में भटकने के बाद इसे डॉ.मनमोहन सिंह सरकार 2006 में अंजाम पर पहुंचा पायी है। अमल आरंभ हो चुका है और मध्यप्रदेश इसमें अग्रणी बन चुका है।

यह सच है कि अनुसूचित जनजातियों, वनवासियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक उन्नयन में व्यावहारिक अवरोधकों पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने समग्र रूप से विचार किया और चिंता व्यक्त की। इसके लिए जनजातीय अध्ययन दल का गठन किया गया। इसमें जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने के साथ चिंतकों और विचारकों को भी अध्ययन दल में शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय महासचिव अर्जुन मुंडा अध्ययन दल के संयोजक, पूर्व केन्द्रीय अनुसूचित जनजाति मंत्री जुएल उराव, फग्गन सिंह कुलस्ते, अनंत नायक सदस्य और भूपेन्द्र यादव दल के सदस्य सचिव मनोनीत किये गये. मार्गदर्शक के रूप में बाळ आपटे और बापू आपटे अध्ययन दल से संबद्ध किये गये हैं। अध्ययन दल की आनन–फानन में भोपाल में पिछले दिनों जो बैठक हुई उसमें मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनजाति कल्याण से जुड़े शासकीय, अशासकीय, जनप्रतिनिधियों ने पूरे मनोयोग से भाग लिया। अध्ययन दल की मुख्य अनुशंसा थी कि सदियों से शोषित पीड़ित जनजाति परिवारों की प्रगति की राह में जो भी रोढ़े हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए हमें अब उनकी राह बनना पडेगा।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा, बापू आपटे, मध्यप्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह, छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ननकी राम कंवर, मध्यप्रदेश के भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री माखन सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव भूपेन्द्र यादव ने चर्चा में भाग लिया। जो खास अनुशंसाएं की गयी, उनमें सबसे प्रमुख पैसा कानून को व्यापक परिप्रेक्ष्य में अमल में लाने की आवश्यकता रेखांकित की गयी।

सदस्यों का मानना था कि पंचायत व एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया कानून के अमल से जनजाति अंचल की ग्राम सभाएं इतनी सशक्त होंगी कि इन समुदायों के हकों का गैर वाजिब शोषण समाप्त हो जावेगा। इसी तरह राज्यों में जनजाति मंत्रणा परिषद का संवैधानिक ढांचा बनाने का संविधान ने प्रावधान किया है। जनजाति मंत्रणा परिषद को इतनी शक्तियां प्रदत्त है कि इनके सक्रिय होने पर जनजाति समुदाय को किसी से अपना हक मांगने नहीं जाना पड़ेगा। प्रश्न यह है कि इन दोनों

मामलों में कहां क्या अवरोध है, इसकी समीक्षा उच्च स्तर पर अब तक क्यों नहीं की गयी? जनजाति क्षेत्रों के पिछड़ेपन जनित असंतोष के कारणों को अकादमिक आधार पर बहस का मुद्दा बनाने के बजाय समाज सुधार को मूर्त रूप देना होगा। जनजाति क्षेत्रों में वैचारिक रचनात्मक आंदोलन खड़ा करने के लिए मंडल स्तर पर कुप्रवृत्तियों का आक्रामक ढंग से सामना करने के लिए सेवाभावी कार्यकर्ताओं का ढांचा खड़ा करना पड़ेगा।

ट्रायबल फास्ट ट्रेक कोर्ट, ट्रायबल भूमि अधिग्रहण विशेष पैकेज, विधिक सहायता में पूर्णता, वन भूमि अधिकार पत्रों के वितरण की सामयिक समीक्षा, जिला योजना मंडल की बैठकों की तरह ही जनजाति समुदाय की समस्याओं के निवारण के लिए अनिवार्य बैठकों का जिलावार प्रावधान करना आवश्यक है। शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि आदिवासी भूमि अधिग्रहण के मामले में 30 वर्ष तक आजीविका की गारंटी अथवा इसी अवधि में हर माह चार हजार रुपये आजीविका राशि के रूप में दिया जाना चाहिए।

मध्यप्रदेश में 5 लाख रु. एकड़ से कम में भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने नशा मुक्त गांव बनाने के लिए प्रोत्साहित किये जाने की सलाह भी दी। नक्सलवाद की आंच से बचाने के लिए जनजाति अंचल का सम्मान बचाना होगा। जनजातियों के लिए आर्थिक, सामाजिक कवच आवश्यक है। नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति संवेदना नाकाफी है उन्हें बराबरी का हक मिलना चाहिए। यह सभी का कर्तव्य बन जाना चाहिए। वनवासी क्षेत्र के किशोर युवक नक्सलियों के हस्तक न ही बनने पाए इसके लिए उनके हाथों में लाभप्रद काम सौंपना होगा। विश्वास का दीपक जलाना है। प्रभात झा ने कहा कि वनवासियों का स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान रहा है। उनकी शौर्य गाथाओं को प्रचारित कर उनके सुषुप्त गौरव और कर्तव्यबोध को जगानेके लिए सामाजिक बहस आरंभ कर उनसे संवाद आरंभ करना है। जनजातीय अध्ययन दल ने वनवासी जीवन की विविधता, उनके समृद्ध अनुभवों, परंपरागत कौशल, बुद्धि वैभव, वनवासियों के जीवन में लाचारी, उनकी आंचलिक आकांक्षाओं का गहन अध्ययन कर उनकी महत्वाकांक्षाओं के अनुशीलन, समाधान के लिए समूचे देश को चार जोनों में विभाजित किया है।

वन संपदा खनिज संपदा में वनवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का फार्मूला ईजाद किया जाता है तो असंतोष और कुंठा को रोका जा सकेगा। उनमें वंचित होने के बजाय स्वामित्व का भाव बना रहेगा। आज जो असंतोष चिंगारी के बाद दावानल बन रही है, उसे भागीदारी, सहयोगी का भाव जगा कर अच्छी तरह शमन किया जा सकता है।

जनजातीय अध्ययन दल देश की लंबाई–चौड़ाई को नापता हुआ आदिवासी बहुल अंचल के जिलों, जनपदीय अंचलों तक में पहुंचेंगे और गहरायी से जांच–पड़ताल कर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को सौंपेंगा जिस पर पार्टी फोरम के अलावा राजनीतिक दलों से मशविरा कर अपनी अनुशंसाएं राष्ट्रपति, केन्द्र सरकार को सौंपेगा। आशा की जाती है कि जनजातीय अध्ययन दल सुदूर अंचल में वनवासियो के मन में वंचना जनित अलगाववाद की ग्रंथि को खोलने में सफल होगा। आज विचारक, बुद्धिजीवी भी इस बात पर एक मत है कि वनवासियों के मन में कहीं न कहीं कुंठा जन्म ले रही है जिसे राष्ट्र विरोधी तत्व बारुद के रूप में इस्तेमाल करने का अवसर खोज रहे हैं।

अध्ययन दल के सामने कुछ आँख खोलने वाले तथ्य बापू आपटे ने पेश किये, जो समस्या के समाधान के प्रयासों में क्रांति ला सकते हैं। उनका मानना है कि सरकार इस विरोधाभास को स्वीकार करे कि जो देश में सबसे विपन्न वंचित (आदिवासी) है, वही रत्न गर्भा भूमि के निवासी हैं। वन संपदा उनकी सहचर है। खनिजों और वनसंपदा को दोहने के लिए उन्हें ही विस्थापित कर शरणार्थी बना दिया जाता है। उनकी करुण गाथा से कोई अपरिचित नहीं है।

उत्खनन के काम आने वाली भूमि हमेशा पट्टे पर दी जावे जिससे वनवासियों का स्वत्व बना रहे. कोयला, अन्य खनिज निकालने के बाद भूमि को परित्यक्त मान लिया जाता है। यदि आदिवासियों का उस पर स्वत्व बना रहता है तो पट्टा की अवधि समाप्त होने पर वे काबिज होकर भूमि का श्रृंगार कर आजीविका से जुड़े रहेंगे। वनवासी क्षेत्रों में ठेकेदारी प्रथा ने शोषण, उत्पीड़न, संस्कृति के प्रदूषण के द्वार खोले हैं। इन्हें बंद करना होगा। वन संपदा खनिज संपदा में वनवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का फार्मूला ईजाद किया जाता है तो असंतोष और कुंठा को रोका जा सकेगा। उनमें वंचित होने के बजाय स्वामित्व का भाव बना रहेगा। आज जो असंतोष चिंगारी के बाद दावानल बन रही है, उसे भागीदारी, सहयोगी का भाव जगा कर अच्छी तरह शमन किया जा सकता है। ■

लोकतंत्र की रक्षा के लिए नक्सलियों से आर-पार की लड़ाई अनिवार्य : डॉ. रमन सिंह

Nत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने एक बार फिर कहा है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए नक्सलियों से आर–पार की लड़ाई अनिवार्य हो गयी है। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि जब तक नक्सलवादी बन्दूक छोड़ कर भारतीय संविधान पर आस्था नहीं जताते और लोकतांत्रिक तौर–तरीकों को नहीं अपनातेए तब तक उनसे बातचीत निरर्थक ही रहेगी। डॉ. रमन सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित देश के नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की विशेष बैठक में यह भी दोहराया कि नक्सलवाद और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू है। डॉ. रमन सिंह ने बैठक में राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के दो नये जिलों बीजापुर और नारायणपुर तथा तीन नये पुलिस जिलों – बलरामपुर, सूरजपुर और गरियाबंद के लिए प्रत्येक जिले के हिसाब से दो सौ करोड़ रूपए के विशेष पैकेज की भी मांग रखी।

उतर चुका है नक्सलियों का मुखौटा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलवादियोंए उनके सहयोगियों और हमदर्दों र्की कथनी और करनी को जनता के समाने लाने का जो सिलसिला छत्तीसगढ़ में छह साल पहले शुरू हुआ थाए उसके कारण अब नक्सलियों का मुखौटा पूरी तरह उतर चुका है। उनकी हिंसक गतिविधियों से यह स्पष्ट हो गया है कि माओवादियों द्वारा आम आदमी के हित में बातें करना एक छलावा है। हकीकत यह है कि उनके द्वारा आम आदमी ही मारा जा रहा है। विकास की हर इकाई को ध्वस्त किया जा रहा है। इसलिए हमने नक्सलियों सख्ती से निपटने की नीति बनायी है। हमने सरकार में आते ही यह मन बना लिया था कि उनसे आर–पार की लड़ाई लड़नी होगी। देश कोए उसके संवैधानिक ढांचे कोए लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए

यह अनिवार्य है। डॉ. रमन सिंह ने यह भी कहा कि अब देश को इस दुविधा से उबरना होगा कि यह किसी राज्य विशेष अंदरूनी मामला है। प्रधानमंत्री ने भी इसे देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है और हमने भी इससे निबटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित रणनीति की जरूरत बतायी है।

नक्सल हमदर्दों के दुष्प्रचार का जोरदार खण्डन

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की बैठक में अपनी बात रखते हुए नक्सलियों और उनके हमदर्द कुछ बुद्धिजीवियों के इस दुष्प्रचार का जोरदार शब्दों में खण्डन किया कि बस्तर में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और निजी उद्योगपतियों को मूल्यवान खनिजों से भरी जमीनें दी जाती है। डॉ. रमन सिंह ने बैठक में कहा कि वस्तु स्थिति यह है कि पिछले 50 साल में कोई भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी एक किलो लौह अयस्क भी नहीं ले गयी है। लगभग 40 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले बस्तर अंचल में सिर्फ एक प्रतिशत जमीन खनिजों के उत्खनन और प्रॉसपेक्टिंग के लिए दी गयी हैए वह भी सिर्फ राष्ट्रीय खनिज विकास निगमए भारतीय इस्पात प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि वास्तव में यह दुःख का विषय है कि नक्सलियों की हिंसक और अराजक पृष्ठभूमि के बावजूद आज भी कुछ लोग उनकी मंशा को लेकर भ्रम की स्थिति में है। प्रजातंत्र में आस्था रखने वाले कुछ ऐसे लोगों और संगठनों की व्यक्तिगत राय में भी नक्सलियों के प्रति सहानुभूति का भाव समय–समय पर उजागर होता रहता है। कई बार तो मुझे लगता है कि कुछ प्रभावशाली प्रबुद्ध लोग जाने–अनजानेए राजनीतिक

परिपक्वता के अभाव में भी नक्सलियों के हमदर्द बन जाते हैं और दूरगामी परिणामों को नजरअंदाज कर उनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं और उनके दुष्प्रचारों से प्रभावित हो जाते हैं।

पूरे देश को एकजुट होने की जरूरत

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल समस्या से निबटने के लिए छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश को बहुआयामी और बहुस्तरीय प्रयासों के लिए एकजुट होने की जरूरत है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी हम सबके सामने है। मुख्यमंत्री ने नक्सल समस्या के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार के नजरिए को स्पष्ट करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ एक नया राज्य हैए जिसके संसाधनों की अपनी सीमा है। एक ओर नक्सलियों ने अपनी सारी ताकत छत्तीसगढ़ में झोंक रखी हैए वहीं दूसरी ओर हमारा नया राज्य नक्सलवाद के खिलाफ आज सबसे बड़ी लड़ाई लड रहा है। हम यह भली–भांति जानते हैं कि नक्सलियों से लड़ने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री से कहा कि जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल हैए तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम नक्सल समस्या के निदान के लिए हर पहलू पर ध्यान दे रहे हैं। पिछड़े क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, बुनियादी सुविधाओं की पहुंच और सामाजिक–आर्थिक समाधानों के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं, जिसके बारे में हमने लगभग हर मंच–हर अवसर पर आपको को अवगत कराया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे प्रयासों का असर वनांचलों की जनता के विश्वास के रूप में सामने आया है।

सड़क निर्माण का लक्ष्य पूर्ण होने तक बी.आर.ओ. की सेवाएं जरूरी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी कहा कि राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और निर्माण कार्यों के लिए विषम परिस्थितियों में भी काम करने में सक्षम सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) की जरूरत हमें अभी भी है। हम चाहेंगे कि जब तक इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाताए तब तक बी.आर.ओ. की सेवाएं हमें मिलती रहे। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास की समन्वित रणनीति बनायी है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की जनसंख्या लगभग 44 प्रतिशत है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अपने वार्षिक बजट का करीब 45 प्रतिशत हिस्सा इन वर्गों के विकास के लिए खर्च कर रही है। इसके अलावा आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में स्थानीय जनता की मांगों और जरूरतों को पूरा करने के लिए दो विशेष प्राधिकरणों का गठन कर उनके माध्यम से बजट के बाहर भी लगभग छह सौ करोड़ रूपए के निर्माण कार्य कराए जा चुके हैं। बस्तर डेव्हलपमेंट ग्रुप का गठन किया गया हैए ताकि नक्सली प्रभावित अंचलों की जरूरतों को पूरा करने और विकास कार्य कराने के लिए फैसले संबंधित जिलों में ही ले लिए जाएं और इनसे संबंधित नस्तियों को राजधानी रायपुर तक भेजने की जरूरत न पड़े।

नये जिलों के लिए विशेष पैकेज जरूरी

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में अधोसंरचना विकास के कार्यों में तेजी आयी है, प्रशासन को आम जनता के और भी ज्यादा नजदीक लाने के लिए दो नए राजस्व जिलों नारायणपुर और बीजापुर का गठन किया गया हैए वहीं तीन नए पुलिस जिले– बलरामपुर, सूरजपुर और गरियाबंद भी गठित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से इन जिलों में समुचित बुनियादी संरचनाओं के विकास के लिए प्रत्येक जिले को दो सौ करोड़ रूपए का विशेष पैकेज स्वीकृत करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद भी दिया कि उनके सहयोग से छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए 4553 करोड़ रूपए की कार्य योजना स्वीकृत की जा रही है।

नक्सल क्षेत्रों में केन्द्रीय बलों के लिए भी जम्मू-कश्मीर की तरह विशेष भत्ते की मांग

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में केन्द्रीय पुलिस बलों के अधिकारियों और कर्मचारियों को अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि इन्हें उन्हीं दरों पर भत्ते और अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिएए जिस दर पर जम्मू और कश्मीर में दी जा रही है। डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री से कहा कि नक्सल हिंसा में शहीद हुए आम नागरिकों और शासकीय कर्मचारियों के लिए भी दस लाख रूपए के मान से अनुग्रह राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। इसके अलावा नक्सल हिंसा में शहीद होने वाले शासकीय कर्मचारियों के परिजनों को केन्द्रीय सेवाओं और संगठनों में नियुक्ति के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। शहीदों के परिजनों और नक्सल प्रभावित जनता को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं देने के विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। छत्तीसगढ़ में हम अपने स्तर पर सुविधाएं जुटाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

विशेष बैठक के लिए प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद

डॉ. रमन सिंह ने प्रारंभ में इस विशेष बैठक के आयोजन के लिए

प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने माओवादियोंए नक्सलवादी तत्वों की मंशा के बारे में छत्तीसगढ़ के साथ देश के अन्य नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के दृष्टिकोण को सही परिप्रेक्ष्य में लिया है। डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री से कहा कि इस मुद्दे पर आपने निरंतर संवाद की प्रक्रिया शुरू की है और उसी के परिणामस्वरूप आज हमें पुनः इस विषय पर अपना नजरिया सामने रखने का अवसर मिला है।

नक्सल सोच की जड़ें तानाशाही स्वरूप में

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मेरी यह स्पष्ट धारणा है कि नक्सलवाद और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम निर्माण करते जाएं और नक्सलवादी विध्वंस करते रहें, तो सारा विकास कार्य बेमानी हो जाता है। सरकार जो सुविधाएं दूरस्थ गांव वालों के लिए जुटाए, उस पर नक्सली डाका डालते रहें तो हमारे प्रयासों का लाभ नक्सल प्रभावित गांवों के निवासियों को मिलना मुश्किल हो जाता है। हम यह जानते हैं कि माओवादी या नक्सलवादी सोच की जड़ें माओवाद के तानाशाही स्वरूप में है जिसे वह एक क्रूरतम हिंसात्मक युद्ध और आतंक के बल पर हासिल करना चाहते हैं। माओवादियों द्वारा आम आदमी के हित में बातें करना तो बस एक छलावा हैए हकीकत यह है कि माओवादियों द्वारा आम आदमी ही मारा जा रहा हैए उनके द्वारा विकास की हर इकाई को ध्वस्त किया जा रहा है। इसलिए हमने नक्सलवादियों से सख्ती से निबटने की नीति अपनाई। हमने सरकार में आते ही यह मन बना लिया था कि नक्सलियों सेए माओवादियों से आर–पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्योंकि यह लड़ाई न सिर्फ छत्तीसगढ़ को नक्सली आतंक से मुक्त करने के लिये अनिवार्य है बल्कि इस देश कोए उसके संवैधानिक ढांचे कोए प्रजातांत्रिक सोच व प्रजातांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिये भी अनिवार्य है। अब देश को इस दुविधा से उबरना होगा कि यह किसी राज्य विशेष का अंदरूनी मामला है। यही वजह है कि आपने भी इस नक्सलवादी समस्या को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है और हमने भी इससे निबटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित रणनीति की आवश्यकता प्रतिपादित की है।

सहयोग और संसाधनों को बढ़ाने की जरूरत

डॉ. रमन सिंह ने यह भी कहा कि हम राज्य के संसाधनों और केन्द्र सरकार के सहयोग से जितने भी प्रयास कर रहे हैंए उन्हें समस्या की भीषणता के अनुरूप बढ़ाना होगा। यह बात स्पष्ट करने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि नक्सली ताकतों में अब कितना इजाफा हो चुका है। हमारी जानकारी के अनुसार बस्तर में नक्सलियों की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी में कुल 7 डिवीजन, 32 एरिया कमेटी हैं, जिसके तहत करीब 50,000 नक्सली एवं जनमिलिशिया, प्रजातंत्र के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। देश की 40 प्रतिशत से ज्यादा मुठभेड़ बस्तर में हुई है। नक्सली बस्तर को आधार क्षेत्र बनाना चाह रहे हैं। वहाँ पर नक्सलियों की बटालियन बन चुकी है और अब वे अपने ब्रिग्रेड भी बनाने की तैयारी में है। दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमने पुलिस का बजट 268 करोड़ से बढ़ाकर 1019 करोड़ रूपये कर दिया। पिछले छह सालों में पुलिस बल 22000 से बढ़ाकर 49000 कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार हर साल तीन–चार हजार लोगों की भर्ती पुलिस बलों में कर रही है। विगत वर्ष 6700 लोगों की भर्ती की गई थी और इस वर्ष फिर 4000 जवानों की भर्ती की जा रही है। इसके अलावा हमने सुरक्षाबलों को प्रशिक्षित, कुशल और सक्षम बनाने के लिए कांकेर में जंगल वारफेयर कॉलेज खोला। एस.टी.एफ. जैसे सक्षम बल का गठन किया, एन्टी–टेररिस्ट फोर्स का गठन किया, तीन सीएट (काउन्टर टेरेरिज्म एवं एन्टी टेररिस्ट) स्कूल हम केन्द्र सरकार के सहयोग से एक माह के अंदर खोलने जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि समय–समय पर केन्द्र सरकार से मिलने वाली मदद से हमें काफी सहारा मिलता है। लेकिन अभी हमें लम्बी लड़ाई लड़नी है, इसके लिए हमें काफी संसाधनों की आवश्यकता होगी। हमारा अनुमान है कि नक्सलियों के विरूद्ध लड़ाई में कम से कम 10 बटालियनों की तत्काल जरूरत है।

पिछले वर्ष मारे गए ११९ नक्सली

डॉ. रमन सिंह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ चल रही कार्यवाही और उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर हालांकि छत्तीसगढ़ में कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं लेकिन यह भी बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2009 में 119 नक्सली मारे गए हैं, यह संख्या देश में सर्वाधिक है। साथ ही पकड़े और मारे गये नक्सलियों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। यह सब केन्द्रीय एवं राज्य सुरक्षा बलों के अथक परिश्रम एवं बलिदान से ही संभव हुआ है। इस लड़ाई को हमें राजनीतिक सामंजस्य और सामाजिक सहयोग के साथ लड़ना होगा। कुछ मानव अधिकारवादियों, छद्म प्रबुद्ध वर्ग के प्रोपोगेण्डा का सहारा नक्सलियों द्वारा लिया जा रहा है। इस मोर्चे पर भी कारगर जवाबी कार्यवाही करते हुए हमें जनता को सच्चाई बताना होगा। हमारा दृढ़ विश्वास है कि आम जनता के विश्वास और समर्थन से यह लड़ाई निश्चित तौर पर जीती जाएगी।■